बुधवार 07 जनवरी 2026 ■ मूल्य 3.00 ■ वर्ष 03 ■ अंक 292 ■ पृष्ठ 08

गौतमबुद्ध नगर

JBT

जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 मुक्त व्यापार समझौते में कृषि का बचाव | 07 लक्ष्य सेन मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में, मालविका बाहर | हिना खान मुंबई के प्रदूषण से सेहत पर पड़ा बुरा असर 08

सीएक्यूएम कर्तव्यों के पालन में विफल रहा है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था अपने कर्तव्यों का पालन करने में 'विफल' रही है और दिल्ली की सीमाओं पर यातायात जाम कम करने के लिए टोल प्लाज़ा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरण के मामले में दो महीने की मोहलत मांगने पर उसे फटकार लगाई।

न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के रवैये में 'गंभीरता' के अभाव की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कारणों की पहचान करने या दीर्घकालिक समाधान खोजने में आयोग को कोई जल्दी नहीं दिख रही है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए न्यायालय ने पिछले साल 17 दिसंबर को कई निर्देश जारी किए थे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से दिल्ली की सीमा पर स्थित नगर निगम के नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करने को कहा था, ताकि भारी यातायात जाम को कम किया जा सके। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति

जॉयमाल्य बागची की पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दो सप्ताह के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और बिगड़ते प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने सीएक्यूएम को चरणबद्ध तरीके से दीर्घकालिक समाधानों पर विचार करना शुरू करने और विभिन्न हितधारकों के रुख से अप्रभावित रहते हुए टोल प्लाजा के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया।

सुनवाई शुरू होते ही सीएक्यूएम की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हितधारकों के साथ हुई बैठकों के विवरण का हवाला देते हुए टोल प्लाजा के मुद्दे पर दो महीने का समय मांगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि पहला कदम प्रदूषण के कारणों की पहचान करना है और इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

पीठ ने कहा कि क्या आप प्रदूषण के कारणों की पहचान कर पाए हैं? इन दिनों सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारी सामग्री आ रही है, विशेषज्ञ लेख लिख रहे हैं, लोगों की राय आ रही है, वे हमें ईमेल के माध्यम से भेजते रहते हैं। पीठ ने कहा कि भारी वाहन इसमें बड़ा योगदान दे रहे हैं, इसलिए पहला सवाल यह है कि हम इसका समाधान कैसे करें। दो जनवरी को बैठक बुलाना और हमसे कहना कि हम दो महीने बाद आएंगे, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। सीएक्यूएम अपने कर्तव्य के पालन में विफल हो रहा है। न्यायालय ने कहा कि वह मामले को दो सप्ताह से अधिक के लिए स्थगित नहीं करेगा और प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए निरंतर काम करेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि समाधान निकालने के बजाय, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने हलफनामा दायर कर टोल प्लाजा को अपनी आय का स्रोत बताया है। अदालत ने यह भी कहा कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण भी इस मामले में कूद पड़ा है और गुरुग्राम के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में एकत्र रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा आवंटित करने का निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया है। अदालत ने कहा कि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले संभावित परिणामों की जांच किए बिना इलेक्ट्रिक वाहनों को शुरू करने जैसा एकतरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता।

पीठ ने कहा कि कोई ठोस योजना या किसी दीर्घकालीन सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव पेश करने के बजाय, केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(सीएक्यूएम) ने केवल एक वस्तु स्थिति रिपोर्ट दी है, जो दुर्भाग्यवश प्राधिकरण की गंभीरता को दर्शाती नहीं है और अधिकांश ऐसे मुद्दों पर मौन है, जो इस अदालत द्वारा उठाए गए थे। पीठ ने कहा कि सीएक्यूएम किसी भी जल्दी में प्रतीत नहीं होता–न तो वह खराब होती वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कारणों की पहचान कर रहा है और न ही दीर्घकालीन समाधान ढूंढ रहा है। इसलिए हम उन निर्देशों को जारी करने के लिए बाध्य हैं, जो कारणों की पहचान और दीर्घकालीन समाधानों को तेज़ करने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, एक दीर्घकालिक योजना के साथ, बेहतर विकल्प चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा सकते हैं।

पीठ ने पर्यावरणविद एम सी मेहता द्वारा दायर जनहित याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की। इससे पहले, 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान, अदालत ने प्रदूषण संकट को 'वार्षिक समस्या' करार दिया था और इस खतरे से निपटने के लिए व्यावहारिक और कारगर समाधानों का अनुरोध किया था। इसने 12 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश में संशोधन किया और अधिकारियों को उन पुराने वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुमति दी जो भारत स्टेज-चार (बीएस-चार) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

उप्र में एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी दो करोड़ 89 लाख नाम कटे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गयी, जिसमें 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल हैं। यह आंकड़ा पूर्व की संख्या 15.44 करोड़ से लगभग दो करोड़ 89 लाख कम है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गयी है।

इसमें 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता शामिल हैं। पिछले साल 27 अक्टूबर की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे। मसौदा सूची में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं को गिनती के दौरान शामिल नहीं किया जा सका है। सीईओ ने कहा कि अब मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां छह जनवरी से छह फरवरी तक दर्ज करायी जा सकेंगी। इस दौरान लोग सूची में नाम शामिल करने, सुधार करने या आपत्ति करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिणवा ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 46.23 लाख मतदाता (2.99 प्रतिशत) मृत पाए गए, जबकि 2.57 करोड़ मतदाता (14.06 प्रतिशत) या तो स्थायी रूप से बाहर चले गये थे या प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे।

वहीं, 25.47 लाख अन्य मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया। उन्होंने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में अब 12.55 करोड़ मतदाता हैं और इसमें राज्य के सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। रिणवा ने बताया कि इस काम में एक लाख 72 हजार 486 बूथ शामिल किये गये थे। इनमें बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) फार्म भरवाने के लिये मतदाताओं तक पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,76,611 बूथ स्तरीय एजेंटों ने भी इस काम में मदद की। सीईओ ने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की कवायद मूल रूप से 11 दिसंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन लगभग दो करोड़ 97 लाख मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से बाहर हो रहे थे जिसके बाद 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया।

संक्षिप्त खबरें

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीयमंत्री सुरेश कलमाड़ी का पुणे में निधन

मुंबई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीयमंत्री सुरेश कलमाड़ी (82) का आज तडक़े पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में निधन हो गया। कलमाड़ी को इलाज के लिए इस अस्पताल में कुछ दिन पहले भर्ती कराया गया था। वह अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार में पत्नी, बेटा, एक बहू, दो शादीशुदा बेटियां, एक दामाद और पोते-पोतियां हैं। उनका पार्थिव शरीर पुणे में उनके घर कलमाड़ी हाउस में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। सुरेश कलमाड़ी का जन्म 01 मई 1944 को हुआ था। राजनीति में आने से पहले वे वायुसेना में पायलट थे। **(संबंधित खबर पेज-7 पर)**

सोनिया गांधी तबीयत खराब होने पर सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य स्थिर

नई दिल्ली। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। फिलहाल उन्हें चेस्ट फिजिशियन की निगरानी में रखा गया है। सर गंगा राम अस्पताल ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि सोनिया गांधी को सोमवार रात करीब 10 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि जांच में पाया गया कि ठंड और प्रदूषण के कारण उनका ब्रॉन्कियल अस्थमा हल्का बढ़ गया था। अस्पताल ने बताया कि उनकी स्थिति बिल्कुल स्थिर है और वह उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा से करीब 100 करोड़ की हेरोइन बरामद, 2 गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर भारत-पाकिस्तान सीमा पर किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान 19.980 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस वर्ष नशे के सौदागरों के खिलाफ यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत हेरोइन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने आज सुबह एक्स पोस्ट में इसका विवरण साझा कर इस कामयाबी की जानकारी दी। पुलिस को प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपितों के संबंध पाकिस्तान के तस्करों हैं। यादव ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और सीमा पार तस्करों की पहचान करने, आपूर्ति मार्गों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को नष्ट करने के लिए जांच जारी है।

मणिपुर में हुए दोहरे धमाकों की जांच एनआईए के जिम्मे

इंफाल। मणिपुर पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 5 जनवरी को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुए दोहरे धमाकों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है। फौगाकचाओ पुलिस स्टेशन इलाके के नगाउकोन गांव में हुए लगातार धमाकों में दो लोग घायल हो गए थे। पहला धमाका, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से हुआ था, सोमवार की सुबह करीब 5.45 बजे एक खाली घर में हुआ। दूसरा धमाका करीब 200 मीटर दूर सुबह करीब 8.45 बजे हुआ।

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयान से बढ़ी चिंता, यूरोपीय देशों ने समर्थन में दिखाई एकजुटता

कोपेनहेगन/ब्रसेल्स। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के बाद यूरोप में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है।

फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और उसके भविष्य से जुड़े फैसले केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही ले सकते हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो सहयोगियों के साथ सामूहिक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। नेताओं ने यह भी रेखांकित किया कि नाटो पहले ही आर्कटिक को प्राथमिकता वाला क्षेत्र मान चुका है और यूरोपीय सहयोगी वहां अपनी मौजूदगी, गतिविधियों और निवेश को बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी खतरे को रोका जा सके। हाल के हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर यह दोहराया है कि वह ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की थी।

ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सैन्य सुरक्षा के लिहाज से अहम है और डेनमार्क उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा। वेनेजुएला में हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद यह आशंका और गहरी हो गई है कि ग्रीनलैंड भी इसी तरह के दबाव का सामना कर सकता है। हालांकि, ग्रीनलैंड के नेताओं ने साफ किया है कि वे अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क को पूरे यूरोप का समर्थन हासिल है।

आदर्श नगर में DMRC स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग, मेट्रो असिस्टेंट इंजीनियर समेत तीन की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में स्थित डीएमआरसी स्टाफ क्वार्टर में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। सेकंड फ्लोर पर अचानक आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मेट्रो के एक असिस्टेंट इंजीनियर, उनकी पत्नी और उनकी दस साल की मासूम बेटी शामिल हैं। हादसे के समय पूरा परिवार फ्लैट के अंदर सो रहा था।

जानकारी के अनुसार, आग लगने की सूचना फायर कंट्रोल रूम को रात करीब 2.39 बजे पर मिली। सूचना मिलते ही पास के फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना की गईं। जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के बाद फ्लैट के अंदर सर्च ऑपरेशन किया गया, तो वहां से तीन लोगों के शव बरामद हुए। इस दौरान आग बुझाने में लगे एक फायरकर्मी को भी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने कहा, "हमें रात 2:39 बजे आग लगने की

सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो आग काफी फैल चुकी थी।

आग पर काबू पाने के बाद जब अंदर जांच की गई, तो तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं, पुलिस को इस घटना की जानकारी करीब रात 3 बजे के आसपास मिली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पहले फ्लैट के अंदर धुआं भरा और उसके बाद तेज ब्लास्ट हुआ, जिससे आग और भी भड़क गई। हालांकि, ब्लास्ट किस वजह से हुआ, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। शॉर्ट सर्किट, गैस लीक या किसी अन्य तकनीकी वजह से आग लगी, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बन कर तैयार आरडीएसओ ने शुरू किये अंतिम परीक्षण

जींद। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो गयी है और इसे पटरी पर उतारने से पहले रेलवे की तकनीकी टीम ने मानकों के आधार पर अंतिम परीक्षण शुरू कर दिये हैं।

लखनऊ स्थित रेलवे के अभिकल्प, विकास एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के तकनीकी अधिकारी फिलहाल ट्रेन संचालन को लेकर हर बारीक पहलू पर काम कर रहे हैं। इस विशेषज्ञ टीम ने ट्रेन की टेस्टिंग की। टीम का मुख्य फोकस पावर कार और उससे जुड़े सुरक्षा एवं नियंत्रण उपकरणों पर रहा। स्पीड सेंसर, कंट्रोल सिस्टम को अलग-अलग गति पर परखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेन निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से संचालित हो सके।

टेस्टिंग के दौरान ट्रेन को धीमी और मध्यम गति पर चला कर उपकरणों की कार्यक्षमता को रिकार्ड

किया गया। इसके अलावा ट्रेन के पायदानों की मजबूती और ऊंचाई की भी जांच की गई। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली इस ट्रेन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस ट्रेन को ईंधन आपूर्ति के लिए जींद में स्थापित किए गए हाइड्रोजन प्लांट को अंतिम कमीशनिंग एवं नियमित संचालन के दौरान स्थिर और निर्बाध 11 केवी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्लांट की वर्तमान विद्युत आपूर्ति स्थिति, बैकअप व्यवस्थाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। इसके लिए बिजली आपूर्ति प्रणाली की नियमित समीक्षा की जाए और वैकल्पिक व्यवस्था और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को भी सुदृढ़ रखा जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के लिए जींद में तीन हजार किलोग्राम भंडारण क्षमता का देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है, जो अब कमीशनिंग के अंतिम चरण में है। यह प्लांट 24 घंटे आधार पर संचालित होगा।

इंदौर में दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

शहर की छवि देशभर में धूमिल हुई

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारी के मामले में उच्च न्यायालय ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा, बहुत दुखद है। देश ही नहीं विदेश तक में शहर की छवि बिगड़ी है।

देश का नाम खराब हो रहा है। दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से हुई मौतों को लेकर उच्च न्यायालय में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में मरीजों के निशुल्क उपचार, मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने जैसी मांगें की गई हैं। पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। मंगलवार को उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। इसमें दूषित पानी से जुड़ा मामला प्रमुख रूप से उठाया गया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस घटना ने शहर की छवि

को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से यह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में जरूरत पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी। अदालत ने संकेत दिए कि यदि पीड़ितों को मुआवजा कम मिला है तो उस पर भी उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही उच्च न्यायालय ने दूषित पानी से प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और पूरे मामले में हुई मौतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी : सीएम

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी जो आज भी हमें सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है।

रेखा गुप्ता ने शहीदी दिवस पर सदन में चर्चा में कहा कि यह महान समागम सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस मनाया गया जो गुरु साहब की मेहरबानी से संभव हुआ है। इसमें लाखों लोगों ने उस समागम में हिस्सा लिया। जिस लाल किला से गुरु साहब से फरमान दिया गया उसी स्थान से गुरबानी के सुर सुनाई दे रहे थे और हजारों लोग लंगर चख रखे थे, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु साहब की शहादत पर वर्तमान पीढी की तरफ से नमन कर पाये। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है। इस महान बलिदान को जन जन तक पहुंचाने सभी के सहयोग से संभव हुआ है। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसे कभी भी भविष्य में याद नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि जिसे अपने पुरुखों पर नाज नहीं है उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचता है। विकास और विरासत के मार्ग पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। इस तेज रफ्तार जिंदगी में करोड़ों लोग अपने गांव और शहर से दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं इसलिए उनको अपने जड़ों से जुड़ने का हक है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करती है। इसी प्रकार कांवड़ यात्रा में दिल्ली सरकार ने पूरी सुविधाएं दी।

सरकार ने हर राज्य के स्थापना दिवस को बड़े गर्व से मनाया। हमने पहली बार भव्यता के दिवाली मनाया। दिल्ली का अपना बहुत बड़ा इतिहास है। दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यह भारत की आत्मा है। पिछले ग्यारह महीने में हमने दिल्ली शहर को मिनी इंडिया का रूप दिया। दिल्ली सरकार हर त्योहार को सिर्फ मनाती नहीं बल्कि उसे जीती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए अपना शीश दिया। यह आज भी हमें सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है। गुरु साहब के एक पंथ के गुरु नहीं थे बल्कि भारत के साझा संस्कृति और मूल्यों प्रखर रक्षक थे। उनके जैसा व्यक्ति बिरले ही समाज में आता है जिसने अपना परिवार खो दिया। उनका जीवन एक कालखंड की कहानी नहीं बल्कि यह मानवता के साहस और धर्मनिष्ठा का शाश्वत आदर्श है। समय समय पर गुरुओं का याद करना हम सबका फर्ज है। गुरु तेग बहादुर सिंह को हिंद का चादर कहा गया।

उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की जनता के साथ लगातार जुड़कर एक परिवार की तरह काम करते रहेंगे। दिल्ली वासियों के सुख दुख में खड़े रहेंगे। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने नियम 270 के तहत गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर सदन में वक्तव्य रखते हुए कहा कि देश दुनिया में गुरु तेगबहादुर की 350 साल के शहादत को मनाया जा रहा है। उन्होंने मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इससे बड़े बलिदान का इतिहास दुनिया में कोई नहीं मिला है। उनके शहादत ने सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को एक अहम संदेश देने का काम किया। उनके शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किला में एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें देश विदेश से लोगों ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुये।

पर्यावरण मंत्री मनजिंद्र सिंह सिरसा ने गुरु तेगबहादुर के महान शहादत को इस सदन में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी का धन्यवाद किया। मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुर को धर्म बदलने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। उन्हें डराने की कोशिश की लेकिन वह किसी भी अत्याचार की परवाह किये बिना शहादत दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गुरु तेगबहादुर के 350 साल शहीदी अवसर पर समारोह मनाकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। गुरु तेगबहादुर ने मानवता और धर्म की आजादी के लिए शहादत दी थी। इस देश की आजादी के बाद किसी ने गुरु तेगबहादुर को याद नहीं किया गया न ही साहबजादों को याद किया गया। दिल्ली के अन्दर बाबर और औरंगजेब के नाम पर सड़कों का नाम रखा गया, यह कैसी मानसिकता थी। हमें किताबों में भी मुगलों के बारे में बढाया गया। जिन लोगों ने इस देश की अस्मिता को मारा उसके बारे में पढाया जा रहा है लेकिन गुरु तेगबहादुर के बारे में नहीं पढाया गया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहली बार सिख गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा शुरू की है। भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि गुरु तेगबहादुर की 350वीं शहीदी दिवस जिस प्रकार मनाया गया उसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कला संस्कृति मंत्री का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जिस प्रकार इस कार्यक्रम में सक्रिय रही उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेगबहादुर की शहादत की दुनिया में कोई दूसरा मिसाल नहीं है।

मुगल शासक ने चार महीने तक गुरु तेगबहादुर को यातना दी लेकिन वह टस से मस नहीं हुये। आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र कादियान ने कहा कि शहीदी दिवस जो मनाया गया वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सिख भाइयों ने जो सेवा की वह गुरुओं के बताये गये रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक पर्व मनाया जाना चाहिए इससे अच्छा संदेश जाता है। हर आदमी अपने हिसाब से त्योहार मनाया जाता है इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। पंजाब की सरकार ने जगह जगह भव्यता के साथ शहीदी दिवस मनाया गया। हमें गुरु तेगबहादुर की शिक्षा पर अमल करना चाहिए न कि सिर्फ उनकी तारीफें करनी चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि गुरुओं की कुर्बानी पूरी दुनिया के लिए हुआ था इसलिए सभी को उनके लिए नतमस्तक होना चाहिए।

भाजपा विधायक तरविन्द्र सिंह मारवाह ने कहा कि गुरु तेगबहादुर ने अपनी कुर्बानी के साथ साथ अपने परिजनों की कुर्बानी दी है। पूरी दुनिया के इतिहास में एक भी परिवार ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी गयी जितनी कुर्बानियां गुरु तेग बहादुर के परिवार ने दी थी। गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए दी है। सिख समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे गुरुओं ने किया है। मुगल शासकों से गुरुओं ने कड़ा मुकाबला किया था। आप के अजय दत्त ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को दिल्ली के साथ ही पंजाब सरकार ने धूमधाम से मनाया जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि इस देश में जब जब जुल्म हुआ है सभी जाति धर्मों के लोगों ने संघर्ष की और शहादत दी है। भाजपा के विधायक राज कुमार भाटिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को लाल किला में समागम मनाना सराहनीय कदम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया अन्याय खिलाफ लड़ने का संदेश दिया गया। समाज के हर वर्ग ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे दिल्ली की जनता को अपने गुरुओं की शहादत को जानने का मौका मिला।

संक्षिप्त खबरें

हत्या की गुत्थी सुलझी तीन आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी और हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वेलकम पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान सुहैल उर्फ जादू (20), इलमान (22) और रिजवान उर्फ कीड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, तीनों का मृतक और घायल युवक के साथ पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक, 5 जनवरी की रात करीब 10 बजकर 2 मिनट पर थाना वेलकम को कूड़ा खट्टा, पीली मिट्टी इलाके में चाकूबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को दो युवक घायल अवस्था में मिले। जिन्हें तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने अरमान (18), निवासी जनता मजदूर कॉलोनी, वेलकम को मृत घोषित कर दिया। जबकि दूसरा घायल अल्ताफ अली (18) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। साथ ही आरोपितो की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान इंस्पेक्टर रूपेश खत्री के नेतृत्व में टीम को अहम सुराग हाथ लगे। जिसके आधार पर तीनों संदिग्धों को दबोच लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनका मृतक अरमान और घायल अल्ताफ अली के साथ पहले से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया।

त्रिलोकपुरी में 17 वर्षीय छात्र की पीट-पीटकर हत्या

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में लगातार सामने आ रही हत्याओं की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। लक्ष्मी नगर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या और वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद अब त्रिलोकपुरी इलाके से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 17 वर्षीय छात्र को कुछ लड़कों के समूह ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात थाना मयूर विहार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से सूचना मिली थी कि मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक युवक को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र इंद्रा कैंप का रहने वाला था और कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की दादी संतोष का आरोप है कि कुछ लड़के उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जहां उसके साथ मारपीट की गई।

महापौर ने केशव पुरम क्षेत्र का किया निरीक्षण

नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के दिए निर्देश

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को बी-3 ब्लॉक, केशव पुरम क्षेत्र का शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय पार्षद योगेश वर्मा के साथ निरीक्षण किया।

इस अवसर पर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने महापौर के समक्ष साफ-सफाई, सार्वजनिक सुविधाओं, रखरखाव एवं अन्य स्थानीय मुद्दों से जुड़ी अपनी समस्याएं रखीं। महापौर ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने डीडीए के एक खाली पड़े प्लॉट में लंबे समय से पड़ी गंदगी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिससे क्षेत्र में अस्वच्छता फैल रही थी।

विधानसभा में मास्क को लेकर किसी को नहीं किया निष्कासित, आतिशी ने किया गुमराह : विजेंद्र गुप्ता

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्य आतिशी द्वारा मीडिया को गुमराह किया गया है और सदन को भ्रमित करने वाले बयान दिए गए हैं।

उनके द्वारा कहा गया कि आज सदस्यों को केवल मास्क पहनने के कारण विधानसभा से बाहर कर दिया गया पूर्णतः असत्य है और सदन की वास्तविक कार्यवाही को प्रतिबिंबित नहीं करता है। चार विधायकों (संजीव झा, सोम दत्त, कुलदीप कुमार एवं जरनैल सिंह) को सदन से निलंबित किए जाने का एकमात्र कारण कार्यवाही में जानबूझकर किया गया व्यवधान था।इस कार्रवाई का मास्क पहनने से कोई संबंध नहीं था। किसी भी स्तर पर किसी सदस्य को केवल मास्क पहनने के कारण न तो निष्कासित किया गया और न ही निलंबित। इस प्रकार के दावे तथ्यों का घोर गलत प्रस्तुतीकरण हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सदन की गरिमा, अनुशासन एवं अधिकार बनाए रखने के उद्देश्य से तथा दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के पूर्णतः अनुरूप लिया गया। सदन की अवमानना की श्रेणी में आने वाले आचरण को देखते हुए, इस विषय को नियम 82 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है। उक्त नियम के अनुसार अध्यक्ष किसी भी विशेषाधिकार या अवमानना से संबंधित प्रश्न को जांच, परीक्षण या प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं तथा सदन को इसकी सूचना दे सकते हैं। यह संदर्भ पूर्णतः नियम की भावना और दायरे में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नियम 221 के तहत विशेषाधिकार समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह परीक्षण करे कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है, उल्लंघन की प्रकृति क्या है तथा उससे जुड़ी परिस्थितियों का परीक्षण कर उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त, यह भी रिकॉर्ड पर रखा जाना आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्य आतिशी ने 'दिल्ली में प्रदूषण' के विषय पर चर्चा आरंभ करने का प्रयास उस समय किया, जबकि यह विषय पहले से ही 7 जनवरी 2026 को चर्चा हेतु कार्यसूची में सूचीबद्ध था। अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त विषय को निर्धारित समय पर लिया जाएगा। इसके बावजूद, सूचीबद्ध कार्य से पूर्व इस मुद्दे को उठाने का प्रयास सदन की सुव्यवस्थित कार्यवाही में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करने और निर्धारित कार्यक्रम को बाधित करने का एक सोचा-समझा प्रयास माना गया है। अध्यक्ष द्वारा की समस्त कार्रवाई संविधान, नियमों एवं सदन की परंपराओं के अनुरूप है तथा सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

आप नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदूषण के खिलाफ किया प्रदर्शन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने मंगलवार को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मास्क पहन कर विधानसभा के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है, अस्पताल भरे हुए है, लेकिन दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग करती है तो बहाने बनाकर चर्चा से बचती है। आतिशी ने सवाल उठाया कि आखिर यह सारा ड्रामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल के महान खिलाड़ी मेसी जब दिल्ली में आए तो स्टेडियम में एक्यूआई के नारे लगे थे। यह केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की बेइज्जती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदूषण पर चर्चा से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि उनके पास इस समस्या का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रही है लेकिन सरकार कुछ नही करना चाहती। आतिशी ने मांग की कि यह दिखावटी राजनीति तुरंत बंद की जाए और प्रदूषण के मुद्दे पर तत्काल गंभीर चर्चा कराई जाए।

शिक्षकों के अपमान पर भाजपा ने विस में केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों और नेताओं ने आम आदमी पार्टी (आआपा) पर शिक्षकों का अपमान करने और झूठी राजनीति फैलाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

जेएनयू में सोमवार रात की घटना पर विश्वविद्यालय ने दी पुलिस को शिकायत

नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) सुरक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस को सबरमती हॉस्टल के बाहर कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में शिकायत दी है। घटना सोमवार(5 जनवरी) रात की है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जेएनयू सुरक्षा विभाग की ओर से आज इस संबंध में वसंत कुंज (नॉर्थ) थाना प्रभारी को पत्र भेज एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि 5 जनवरी की रात करीब 10 बजे सबरमती हॉस्टल के बाहर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसे जेएनयू में 5 जनवरी 2020 को हुई हिंसा की छठी बरसी के रूप में बताया गया। कार्यक्रम का शीर्षक "ए नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गोरिल्ला ढाबा" था और इसमें लगभग 30–35 छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन की ओर से आयोजित किया गया था।

पत्र के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत में

जेएनयू में सोमवार रात की घटना पर विवि ने दी पुलिस को शिकायत

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) सुरक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस को सबरमती हॉस्टल के बाहर कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में शिकायत दी है। घटना सोमवार(5 जनवरी) रात की है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जेएनयू सुरक्षा विभाग की ओर से आज इस संबंध में वसंत कुंज (नॉर्थ) थाना प्रभारी को पत्र भेज एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि 5 जनवरी की रात करीब 10 बजे सबरमती हॉस्टल के बाहर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसे जेएनयू में 5 जनवरी 2020 को हुई हिंसा की छठी बरसी के रूप में बताया गया। कार्यक्रम का शीर्षक "ए नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गोरिल्ला ढाबा" था और इसमें लगभग 30–35 छात्र मौजूद थे। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन की ओर से आयोजित किया गया था। पत्र के अनुसार, कार्यक्रम की शुरुआत में यह आयोजन केवल बरसी मनाने तक सीमित प्रतीत था। हालांकि बाद में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर आए न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वर बदल गया। आरोप है कि इस दौरान कुछ छात्रों द्वारा अत्यधिक आपत्तिजनक, उकसाने वाले और भड़काऊ नारे लगाए गए, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के रूप में बताया गया है। पत्र में नौ छात्रों के नाम भी दिए गए हैं। सुरक्षा विभाग ने कहा है कि इस तरह के नारे लोकतांत्रिक असहमति की मर्यादा के विपरीत है। जेएनयू की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और इससे सार्वजनिक व्यवस्था, परिसर की शांति तथा विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नारे जानबूझकर और बार-बार लगाए गए, जिससे यह आकस्मिक नहीं बल्कि सोची-समझी कार्रवाई प्रतीत होती है।

घटना के समय सुरक्षा विभाग के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे और स्थिति पर नजर रखे हुए थे। सुरक्षा विभाग ने पुलिस से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। इस पत्र की प्रतिलिपि कुलपति और रजिस्ट्रार कार्यालय को भी भेजी गई है।

हत्या के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

नोएडा। नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में रोडरेज (सड़क पर गाड़ी चलाते समय गुस्सा) के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में वांछित दो आरोपितों को मंगलवार सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) सुधीर कुमार ने बताया कि सुबह को थाना दादरी पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी, तभी कैमराला गांव में हरकेश और मोहित के ऊपर हुए घातक हमले के मामले में वांछित दो आरोपितों के मोटरसाइकिल से जीटी रोड से जारचा की तरफ जाने की जानकारी मिली। सूचना के आधार पर चेकिंग कर रही पुलिस ने दो मोटर साइकिल सवारों को आते देखा।

पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे रुकने की बजाए पुलिस टीम पर मोटर साइकिल सवार गोली चलाते हुए भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। एएसपी ने बताया कि

घायलों की पहचान प्रशांत भड़ाना पुत्र गजब सिंह निवासी सिकंदराबाद बुलंदशहर तथा प्रशांत उर्फ सीटू पुत्र विजेंद्र निवासी ग्राम कैमराला के रुप में हुई हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कपिल प्रधान पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम कैमराला ने सोमवार सुबह को थाना दादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके चचेरे भाई मोहित (32)पुत्र धर्मवीर और उनके दोस्त हरकेश उर्फ झंडू (32) पुत्र जतन सिंह कार में सवार होकर रविवार की रात डेढ़ बजे के करीब कैमराला गांव जा रहे थे।

जहां राजवीर के घर के सामने कुछ अज्ञात लड़के एक कार से पहुंचे। उन्होंने उसके भाई की कार रूकवाई और चचेरे भाई मोहित और हरकेश के ऊपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर भाग गए। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां हरकेश की मौत हो गई है। वहीं मोहित की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इसी घटना के उपरोक्त दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है।

संक्षिप्त खबरें

महिलाओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी

नोएडा। मिशन शक्ति अभियान-5.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के थाना क्षेत्रों में मंगलवार को महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा जागरुकता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही साइबर ठगी के प्रकार और इससे बचने के उपायों के बारे में बताया।

परशुराम बने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष

नोएडा। आम आदमी पार्टी (आप) के नए जिलाध्यक्ष परशुराम चौधरी को बनाया गया है। चौधरी सेक्टर-104 हाजीपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्हें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की सहमति से पश्चिमी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका की स्वीकृति से गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रभारी सीएम चौहान ने जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। उन्हें सेक्टर-89 स्थित निम्मी विहार में पार्टी दफ्तर पर मंगलवार को मनोनीत पत्र देकर और फूल-माला पहनाकर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

मकान का ताला तोड़कर नगदी और जेवरात चोरी

ग्रेटर नोएडा। सेक्टर बीटा-1 में बदमाश लगातार घरों में चोरी कर रहे हैं। बदमाश फिर एक घर से नगदी और गहने चोरी कर ले गए। इससे पहले पड़ोसी के घर में चोरी हुई थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेक्टर बीटा-1 के बी ब्लॉक में डॉ. तनुश्री गहलोत परिवार के साथ रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बदमाश सोमवार की रात उनके घर का ताला तोड़कर करीब 25 हजार रुपये, गहने समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। उन्हें मंगलवार की सुबह चोरी के बारे में पता चला। उनके बराबर के घर में भी चोरी हुई। महिला डॉक्टर ने बताया कि एक साल पहले भी उनके घर में चोरी हुई थी। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। चोरों का पता लगाकर घटना का खुलासा किया जाएगा।

सेक्टर 113 में कार की टक्कर से व्यक्ति घायल

नोएडा। सेक्टर-113 थानाक्षेत्र में तेज रफ्तार कार के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क के सामने खड़े व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल को गया। उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाने में दी शिकायत में सलारपुर गांव निवासी राकेश कुमार ने बताया कि बीते माह 24 दिसंबर को दोपहर पौने तीन बजे के करीब उनका भाई रोहित अपनी बाइक से सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष वन सोसाइटी चौराहे के पास गया था। बाइक खड़ी कर वह गजराज मार्केट की एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। इसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन आया और रोहित को टक्कर मारकर चला गया। रोहित के सिर और हाथ में चोटें आईं और वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। राहगीरों की मदद से घायल को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

आरटीई के तहत जिले में 14 हजार सीटों पर दाखिले होंगे

स्कूलों में सीटें घोषित करने के लिए शुरू हुई मैपिंग प्रक्रिया हुई समाप्त

नोएडा। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत जिले के स्कूलों में सीटें घोषित करने के लिए शुरू हुई मैपिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिले के 1264 निजी विद्यालयों में 14 हजार से अधिक सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 103 विद्यालय और एक हजार सीटें बढ़ गई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देश पर नवंबर में आरटीई आवेदन के लिए घोषित की जाने वाली सीटों की मैपिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चली। इसके बाद दिसंबर में प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में आगामी वर्ष में 1264 निजी विद्यालयों में 14 हजार 100 सीटों पर दाखिले दिए जाएंगे। पिछले वर्ष 1161 विद्यालयों में 13 हजार सीटें घोषित की गई थीं। जिनमें से चार चरण में आवेदन करने के बाद 4,267 गरीब विद्यार्थियों को ही दाखिल मिल पाया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि शासन के नए निर्देश के मुताबिक, इस बार विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए पांच चरण मिलेंगे। आवेदक के आधार कार्ड के साथ-साथ माता-पिता का आधार कार्ड भी जरूरी होगा। इसके अलावा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवेदक सिर्फ अपने गांव के स्कूलों में ही आवेदन कर सकते हैं। अपने गांव के बाहर के स्कूलों में आवेदन करने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। बीएसए ने बताया कि एक आवेदन एक बार में सिर्फ एक ही जगह से आवेदन कर सकता है। एक से ज्यादा आवेदन करने पर निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा अगर आवेदन में फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं, तो विभाग कानूनी कार्रवाई भी करेगा।

पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, कंपनी निदेशक समेत 13 गिरफ्तार

नोएडा। नोएडा में साइबर क्राइम थाना पुलिस और थाना सेक्टर 63 पुलिस ने बीती रात को एक संयुक्त कार्रवाई के तहत नोएडा के सेक्टर 63 के एच-ब्लॉक में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए मौके से कंपनी के निदेशक सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस आदि करवाने के नाम पर तथा पॉलिसी को रिन्यूअल करवाने और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे। कॉल सेंटर के माध्यम से दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को ज्यादा शिकार बनाया जा रहा था। अपर पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस और थाना सेक्टर 63 पुलिस ने सेक्टर 63 के एच- ब्लॉक मे स्थित एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की।

पुलिस ने यहां से सुमित कुमार, विवेक कुमार, मोहम्मद सोहेल, ईश्वर ,राज सलाउद्दीन, समीर अहमद, मोहम्मद आसिफ, मिथिलेश कुमार, छत्रपाल, सत्यम, हरिओम, राजीव सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इनके पास से दो लैपटॉप, टेलीकॉलर, 31 मोबाइल फोन तथा अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस करवाने तथा पॉलिसी को रिन्यूअल करवाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रकम फर्जी बैंक अकाउंट में लेते थे। उन्होंने बताया कि ये लोग विभिन्न बीमा कंपनियों के डाटा चोरी करके उनके ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें लुभावनी स्कीम देकर अपने फंसाते थे।

उन्होंने बताया कि पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इस कॉल सेंटर से दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को ज्यादा शिकार बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों ने सैकड़ो लोगों के साथ ठगी करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि जो लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, उनके पास एक वैध कॉल सेंटर चलाने का भी लाइसेंस था। वे अवैध कॉल सेंटर की आड़ में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके।

मोबाइल फोन चोरी करने वाले आठ बदमाश गिरफ्तार

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 12 करोड़ से ज्यादा कीमत के 821 फोन किये बरामद

नोएडा। नोएडा के थाना फेस -2 पुलिस ने आज सुबह एनसीआर के विभिन्न साप्ताहिक बाजारों से लोगों की जेब से मोबाइल फोन चोरी करने वाले गैंग के आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो बाल अपचारी हैं। इनके पास से पुलिस ने चोरी के 821 मोबाइल फोन बरामद किया है। इनमें 51 आईफोन और सैकड़ों कीमती स्मार्ट फोन हैं। सभी बरामद फोन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जोन द्वितीय शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना फेस- दो पुलिस ने आज सुबह एक सूचना के आधार पर प्रदीप कुमार, श्याम कुमार, भारतीय महतो, शेखर विशाल कुमार, गोविंदा महतो, रोहित सैनी और दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इनकी निशानदेही पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न साप्ताहिक बाजारों और भीड़भाड़ वाले

बाजारों से चोरी किए हुए 821 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। डीसीपी ने बताया कि ये बदमाश भीड़भाड़ वाले एरिया में घुस जाते हैं तथा लोगों की जेब से मोबाइल फोन चोरी कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों ने फोन चोरी की 2 हजार से ज्यादा वारदातें करनी स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये लोग चोरी के फोन किसको बेचते थे। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त, 2 वर्ष में 39114 लोगों के हुए चालान

नोएडा। वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने वाले लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। पुलिस ने 2 वर्षों के अंतर 39 हजार 114 वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस की यह कार्रवाई निरंतर जारी है। गाड़ियों में दिए जाने वाले फीचर की तरह अब लोगों ने ब्लैक फिल्म को भी जरूरी मान लिया है। काले शीशे के दुष्प्रभाव जाने बगैर वाहन स्वामी कार खरीदने के बाद उसपर ब्लैक फिल्म चढ़वाने में लग जाते हैं। सड़कों पर दौड़ती हुई करीब हर नौवीं गाड़ी पर ब्लैक फिल्म चढ़ी दिखती है।

ब्लैक फिल्म शीशों पर चढ़वाना प्रतिबंधित है यह जानते हुए भी वाहन चालकों का आकर्षण कम नहीं हो रहा है। पुलिस उपायुक्त यातायात डॉक्टर प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस ने बीते दो साल में 39114 वाहन पर कार्रवाई करते हुए ब्लैक फिल्म उतरवाई हैं। उनके अनुसार वर्ष 2024 में 20,825 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। वहीं वर्ष 2025 में 18,289 वाहनों का चालान किया गया। गाड़ियों पर

ब्लैक फिल्म चढ़वाने पर पांच हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का चालान है। बता दें कि पहले तीस प्रतिशत तक की दृश्यता होने का नियम था, लेकिन अब नियम को संशोधन करते हुए 100 प्रतिशत तक की दृश्यता कर दिया गया है। ऐसे में कार डेकोर की दुकानों से ब्लैक फिल्म चढ़वाना पूरी तरह से अवैध साबित हो सकता है। हालांकि कुछ गाड़ियों को कंपनी फिटेड ही टिंटेड शीशे (काले शीशे) दिए जा रहे हैं। जिनसे दृश्यता पर खासा प्रभाव नहीं पड़ता। डीसीपी ने बताया कि गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगवाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। काले शीशे वाली गाड़ियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसे लगाने से बचना चाहिए।

लिवइन में रह रहे युवक ने जान दी, युवती को जेल भेजा

नोएडा। मामूरा गांव स्थित कमरे में पिछले चार वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक ने रविवार रात फंदे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मूलरूप से जिला प्रतापगढ़ के रामगढ़ी निवासी अतुल कुमार ओझा नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वह युवती गरिमा सिंह के साथ पिछले चार वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। युवती भी कंपनी में नौकरी करते है। दोनों पिछले कुछ समय से मामूरा गांव की गली नंबर-8 स्थित कमरे में किराये पर रहते थे। पुलिस को रविवार देर रात सूचना मिली कि अतुल कुमार ओझा का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ है। अतुल के साथ रहने वाली गरिमा सिंह से पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ दिन पहले ही अतुल को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था। इसको लेकर वह मानसिक रूप से तनाव में था। रविवार रात करीब 11 बजे दोनों कमरे में सो गए थे। देर रात करीब दो बजे जब गरिमा सिंह की आंख खुली तो उसने अतुल को कमरे में फंदे पर लटका देखा। उसने इसकी सूचना पड़ोसियों को दी। पुलिस ने बताया कि अतुल के भाई नवीन कुमार ओझा ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने गरिमा सिंह और अन्य लोगों पर अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गरिमा सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर, पति-पत्नी व दामाद घायल

- 33 किलोमीटर माइलस्टोन के पास रात दो बजे हुआ हादसा
- अज्ञात चालक के खिलाफ जेवर थाने में प्राथमिकी दर्ज

यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात 33 किलोमीटर माइलस्टोन के पास तेज रफ्तार कार ने एक अन्य कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार पति-पत्नी और उनका दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को जेवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायल बदन सिंह निवासी उत्तम नगर, दिल्ली व उनकी पत्नी किरण लता तथा दामाद योगेश कुमार निवासी शमशाबाद, आगरा घायल हो गए। बताया गया कि सभी लोग दिल्ली से आगरा जा रहे थे। रात करीब दो बजे एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रही एक अज्ञात कार के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कार में बैठे तीनों लोगों को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद राहगीरों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पीड़ित के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा, उद्घाटन की तैयारी तेज

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भौतिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट के इसी महीने लोकार्पण की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए अब एयरोड्रम लाइसेंस मिलने और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से उद्घाटन की तिथि तय होने का इंतजार है।

नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विगत दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें आमंत्रण भी दिया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की उपलब्धता के अनुसार जल्द ही उद्घाटन की तारीख घोषित की जाएगी। उद्घाटन के साथ ही यहां से व्यावसायिक उड़ानों का संचालन शुरू हो सकता है। नोएडा एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक बड़ी सौगात होगा। एयरपोर्ट के आसपास औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स, होटल और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए भी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और यमुना प्राधिकरण एयरपोर्ट से जुड़ी सड़क पर साइनऐज और अन्य आधारभूत सुविधाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। सीईओ आरके सिंह का कहना है कि एयरपोर्ट तैयार है। अब पीएमओ से शुभारंभ की तारीख तय होने का इंतजार किया जा रहा है।

संपादकीय

बांग्लादेश में हालात फिर बेपटरी

बांग्लादेश, जो कभी अपने संघर्ष, बलिदान और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के लिए जाना जाता था, आज एक गंभीर संक्रमण काल से गुजर रहा है। हाल के समय में वहां के राजनैतिक, सामाजिक और आंतरिक हालात न केवल बांग्लादेश की जनता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई दिनों से हिंदुओं का कत्लेआम जारी है। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ हिंदू समुदाय के लोगों को निरंतर निशाना बना रही है। सोमवार को बांग्लादेश से राणा प्रताप बैरागी नामक युवक की हत्या के चंद घंटों बाद ही देर रात एक और हिंदू युवक मोनी चक्रवर्ती के कत्ल की खबर सामने आई है। इसके अलावा एक हिंदू विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में बीते 3 सप्ताह के भीतर 6 हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। इन हत्याओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में बदहाल कानून व्यवस्था और अराजकता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कयास लगने लगे हैं कि क्या युनूस के हाथ देश की बागडोर फिसलती जा रही है और वह सत्ता पर नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक हालात और राजनैतिक संकट ने देश के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। यूनुस सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के बजाए इन घटनाओं को हिंसा की छिटपुट घटनाएं बताकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की है। बांग्लादेश में घटित ताजा घटनाक्रम ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया है। पड़ोसी मुल्क के राजनीतिक संकट की आंच भारत तक पहुंच रही है। बांग्लादेश के इस संकट ने जहां भारत की कूटनीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, वहीं दूसरी ओर भारत की सामरिक चुनौती भी बढ़ गई है। बांग्लादेशी शासन को इस बात पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि कट्टरपंथी विचारधारा जब युवाओं के मस्तिष्क पर हावी होती हैं तो एक स्वस्थ लोकतंत्र भी बर्बाद हो जाता हैं। बांग्लादेश को भारत से सीखना चाहिए कि लोकतंत्र और सुशासन की नींव पंथनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य पर ही स्थापित होती हैं। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है लेकिन कट्टरपंथ की आड़ में विरोध एक पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। इस गंभीर मुद्दे को केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहकर टाला नहीं जा सकता। भारत की सदैव यही नीति रही है कि पड़ोसी देश शांत, स्थिर और समृद्ध हों। बांग्लादेश से भी यही अपेक्षा है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और कट्टरपंथ के विरुद्ध कठोर कदम उठाए।

मुक्त व्यापार समझौते में कृषि का बचाव

वहीं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की द्विपक्षीय एफटीए वार्ताएं अलग-अलग चल रही थीं। इस परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही ऐसा देश बचता था, जिसके साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए गंभीर जोखिम माना जा रहा था, और वह देश था चीन। इसलिए भारत ने आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया और इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ अलग-अलग, द्विपक्षीय समझौते करने का रास्ता चुना। जब भारत ने अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए, तो कई लोगों को हैरानी हुई कि कृषि और डेयरी को बाहर रखते हुए यह समझौता कैसे किया गया। हालांकि, इस कदम की व्यापक सराहना भी हुई। अब जब न्यूजीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया गया है, और उसमें भी कृषि तथा डेयरी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, तो यह दृष्टिकोण और अधिक पुष्ट हो जाता है कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय अत्यंत सतर्क रहा है और उसने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और डेयरी को बाहर रखने में सफलता हासिल की है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत जैसे देश के लिए कृषि और डेयरी की सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है।

-डा. अश्विनी महाजन-

नौ कुछ दिन पहले भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ओमान तथा अन्य देशों के साथ भी एफटीए कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को कुछ हैरानी से देखा जा रहा है, जबकि नवंबर 2019 में भारत ने स्वयं को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) से बाहर कर लिया था, जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों शामिल थे। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि भारत ने अब इन्हीं देशों के साथ अलग-अलग एफटीए कैसे कर लिए। आरसीईपी एक प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता था, जिसमें मुक्त व्यापार से जुड़े प्रावधान शामिल थे। इसमें 16 देश- 10 आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत भागीदार थे। इस समझौते पर लगभग आठ वर्षों तक बातचीत चली। आम तौर पर यह माना जाता है कि भारत ने आरसीईपी से बाहर निकलने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि समझौते का अंतिम प्रारूप भारत की अपेक्षाओं और हितों के अनुरूप नहीं था। 4 नवंबर 2019 को आरसीईपी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं देती।

उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षाओं ने उन्हें इस समझौते से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को अंतिम क्षण में इस समझौते से पीछे हटने का साहसिक कदम कैसे लिया? संभवतः यह विश्व इतिहास में पहली बार था जब किसी सरकार के मुखिया ने वर्षों की बातचीत और अंतिम मसौदा तैयार होने के बाद भी, शिखर सम्मेलन में अन्य सभी नेताओं के सामने यह घोषणा की कि उनका देश इस समझौते में शामिल नहीं होगा। वास्तव में, डेयरी और कृषि ऐसे दो प्रमुख क्षेत्र थे, जिन पर भारत ने कठोर रुख अपनाया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मांग थी कि आरसीईपी के सदस्य देश अपने डेयरी और कृषि बाजारों को अन्य देशों के लिए खोलें। आरसीईपी से भारत के बाहर निकलने और बाद में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ अलग-अलग मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने के बीच जो विरोधाभास दिखाई देता है, उसे समझने के लिए आरसीईपी की संरचना को समझना आवश्यक है। आरसीईपी में जो 16 देश शामिल थे, इनमें से 10 आसियान देशों के साथ भारत के पहले से ही मुक्त व्यापार समझौते मौजूद थे। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी भारत के एफटीए पहले से लागू थे।

वहीं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की द्विपक्षीय एफटीए वार्ताएं अलग-अलग चल रही थीं। इस परिप्रेक्ष्य में केवल एक ही ऐसा देश बचता था, जिसके साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए गंभीर जोखिम माना जा रहा था, और वह देश था चीन। इसलिए भारत ने आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया और इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ अलग-अलग, द्विपक्षीय समझौते करने का रास्ता चुना। जब भारत ने अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए, तो कई लोगों को हैरानी हुई कि कृषि और डेयरी को बाहर रखते हुए यह समझौता कैसे किया गया। हालांकि, इस कदम की व्यापक सराहना भी हुई। अब जब न्यूजीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया गया है, और उसमें भी कृषि तथा डेयरी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, तो यह दृष्टिकोण और अधिक पुष्ट हो जाता है कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय अत्यंत सतर्क रहा है और उसने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और डेयरी को बाहर रखने में सफलता हासिल की है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत जैसे देश के लिए कृषि और डेयरी की सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यदि कृषि और डेयरी को मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल किया जाए, तो इससे भारतीय कृषि और डेयरी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। उनका यह भी कहना है कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, तो उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

आजीविका और खाद्य सुरक्षा : संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों से आता है, जिनके पास औसतन केवल एक या दो दुधारू पशु होते हैं। इनके लिए दूध केवल अतिरिक्त आय का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का आधार है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है और 8 करोड़ से अधिक परिवार यानी 36 करोड़ लोग डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके विपरीत, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में डेयरी एक व्यापार-केंद्रित उद्योग है, जहां उत्पादन का उद्देश्य मुख्यतः निर्यात और मुनाफा होता है, न कि व्यापक ग्रामीण आजीविका। निस्संदेह, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। मात्रा की दृष्टि से देखें, तो लीटर में दुग्ध उत्पादन कई प्रमुख कृषि फसलों के किलोग्राम में उत्पादन से भी अधिक है। भारत में अधिक दूध उत्पादन के पीछे प्रमुख कारण यह है कि देश में दुग्ध उत्पादों, विशेषकर दूध, के दाम अपेक्षाकृत लाभकारी हैं, जिससे छोटे उत्पादकों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह भी सर्वविदित है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुग्ध उत्पादों, विशेषकर मिल्क पाउडर, की कीमतों में भारी अंतर है। यदि न्यूजीलैंड का दूध या दूध पाउडर बिना शुल्क के भारत में आने लगे, तो घरेलू बाजार में कीमतों में तेज गिरावट आएगी। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि देश के लाखों छोटे दुग्ध उत्पादक उत्पादन बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बने रहने का दर्जा खो देगा, बल्कि यहां एक गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह कृषि उत्पाद हो या दूध, भारत जैसे विशाल देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है।

अमेरिका के साथ समझौता और कृषि : ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका, दोनों ही, एक व्यापक व्यापार समझौते पर पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा कृषि क्षेत्र बनकर उभरी है। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका, ब्राजील के बाद, सोयाबीन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ट्रंप टैरिफ के बाद चीन, जो अमेरिकी सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक था, ने अमेरिका से आयात में भारी कटौती कर दी है। इसी तरह अमेरिका अन्य कृषि उत्पादों का भी अधिशेष उत्पादन कर रहा है, जिसके लिए वह नए विदेशी बाजार तलाश रहा है। यही कारण है कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि उत्पादों के लिए आक्रामक रूप से प्रवेश चाहता है, जबकि भारत इसका सख्त विरोध कर रहा है। भारत के इस विरोध के पीछे मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, यदि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों को बाजार में प्रवेश की अनुमति देता है, जो अमेरिकी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी से समर्थित हैं, तो भारतीय किसान इस असमान प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाएंगे और उत्पादन बंद करने को मजबूर हो सकते हैं। दूसरा, अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने से भारत की जैव-सुरक्षा और बीज संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

डिब्बों से डिजिटल तक: भारतीय रेलवे का आधुनिक रूपांतरण

-सुनील कुमार महला-

भारतीय रेल देश की जीवनरेखा मानी जाती है और यह भारत के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय रेल की खास बात यह है कि भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा पाठक जानते होंगे कि भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर (वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) से ठाणे के बीच चलाई गई थी तथा यह ऐतिहासिक यात्रा भारतीय रेल के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। पाठकों को बताता चलूं कि इस पहली यात्री ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इसमें करीब 400 विशिष्ट अतिथि सवार थे। ट्रेन को तीन भाप इंजनों-साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया था तथा इस अवसर पर ट्रेन के प्रस्थान के समय 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। बोरीबंदर से ठाणे तक की यह पहली रेल यात्रा न केवल परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्ध हुई, बल्कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की दिशा में एक नए युग की नींव भी बनी।

गौरतलब है कि प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ से अधिक यात्री भारतीय रेल से सफर करते हैं और यह आम लोगों के लिए यातायात का बहुत ही शानदार साधन है। भारतीय रेल देश के लगभग-लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता (सरकारी क्षेत्र) में से एक है। भारतीय रेल का आदर्श वाक्य है-जीवन रेखा, जो इसकी भूमिका को दर्शाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में निर्मित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है। कहना ग़लत नहीं होगा कि रेल के क्षेत्र में हम लगातार प्रगति पर हैं। भारतीय रेल ने बीते कुछ ही वर्षों में आधुनिक तकनीक, तेज़ और सुरक्षित ट्रेनों, बेहतर आधारभूत संरचना तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वंदे भारत जैसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण, डिजिटल टिकटिंग, स्टेशन पुनर्विकास और माल परिवहन में सुधार इस प्रगति के सशक्त उदाहरण हैं। साथ ही, सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने, स्वच्छता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल पहलें अपनाने से रेलवे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभा रही है। निरंतर नवाचार और योजनाबद्ध विकास के साथ भारतीय रेल भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को सशक्त बना रही है। पाठकों को जानकारी देता चलूं कि भारतीय रेल केवल यात्री परिवहन ही नहीं, बल्कि माल ढुलाई में भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दूसरे शब्दों में कहें तो माल ढुलाई के माध्यम से उद्योग, कृषि और व्यापार को गति देती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में सम्मिलित कर दिया गया है तथा भारतीय रेल निरंतर विद्युतीकरण, डिजिटलीकरण और हरित ऊर्जा की दिशा में कार्य कर रही है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वर्तमान में भारतीय रेल का ब्रॉडगेज नेटवर्क लगभग 99 प्रतिशत से अधिक विद्युतीकृत हो चुका है और जानकारी के अनुसार सरकार का लक्ष्य इस साल यानी कि 2026 तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा करना है, जिससे डीज़ल पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में ई-टिकटिंग, यूटीएस(जनरल टिकट हेतु) मोबाइल ऐप, क्यूआर/यूपीआइ आधारित भुगतान, हैंड-हेल्ड टिकट जांच प्रणाली और केंद्रीकृत ट्रैफिक कंट्रोल जैसी व्यवस्थाएँ लागू की जा चुकी हैं, जिससे टिकट बुकिंग क्षमता एक मिनट में 30 हजार से अधिक टिकट तक पहुँच गई है और संचालन अधिक पारदर्शी व कुशल हुआ है। वहीं हरित ऊर्जा की दिशा में भारतीय रेल ने अब तक लगभग 800 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा और 90 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, साथ ही 1600 मेगावाट राउंड-द-क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा के समझौते किए गए हैं। देशभर में 2600 से अधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। इन प्रयासों के माध्यम से भारतीय रेल ने 2030 तक नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो इसे न केवल विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणालियों में, बल्कि सबसे हरित रेल नेटवर्कों में भी शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पाठकों को जानकर आश्चर्य होगा कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने के कारण भारतीय रेल प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा सुविधा प्रदान करती है। सच तो यह है कि भारतीय रेल आज केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन नहीं रही, बल्कि देश में बदलाव और विकास की एक मजबूत शक्ति बन चुकी है। हाल के वर्षों में इसके कामकाज और सोच दोनों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है।

अब रेलवे खुद को नई जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों के अनुसार नए रूप में ढाल रही है। सबसे पहले यदि हम यहां पर आधुनिक ट्रेनों की बात करें, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जल्द शुरू होना और वर्ष 2027 तक बुलेट ट्रेन परियोजना का प्रस्ताव यह दिखाता है कि भारत तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही रेलवे ने देश के उन इलाकों तक भी अपनी पहुंच बनाई है, जो पहले बहुत दूर(रिमोट एरिया) और दुर्गम माने जाते थे। पिछले वर्ष कश्मीर घाटी और मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना सामरिक और विकासात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज भी शामिल है। निश्चित ही इस परियोजना के पूर्ण होने से घाटी में आवागमन, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति मिली है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भैरबी-सैरांग (आइजोल) नई रेलवे लाइन पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह परियोजना पहाड़ी और कठिन भू-भाग में रेल कनेक्टिविटी स्थापित कर मिजोरम को देश के रेल मानचित्र पर सशक्त रूप से जोड़ रही है, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इससे इन क्षेत्रों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से बेहतर हुआ है और वहां के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुले हैं।

इतना ही नहीं, भारतीय रेल ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। समुद्र के ऊपर बना देश का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल पंबन पुल इसका एक बड़ा उदाहरण है। जानकारी के अनुसार यह पुल पाक जलडमरूमध्य पर बना है और रामेश्वरम को दक्षिण भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। वहीं पश्चिम भारत में समर्पित माल ढुलाई गलियारे के तहत वैतरणा से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक 102 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पर पहली मालगाड़ी चलाई गई, जिससे माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाने में मदद मिलेगी।

कर्मकांड तक सीमित रहना धर्म का काम नहीं

धर्म की पूर्णता भगवद्सिद्धि के प्रत्यक्ष मार्ग की प्राप्ति में निहित है, यही वह बात है जो व्यक्ति को पूर्ण मनुष्य बनाने के लिये आवश्यक है।

ऐसा मनुष्य जिसका जीवन पूर्ण समंजस्यता में हो, ऐसा मनुष्य जो अपार प्रज्ञा, सजनशीलता, ज्ञान, शांति और सुख से परिपूर्ण हो। मनुष्य के लिये धर्म की पूर्णता वह स्थिति प्राप्त करने में है, जो विश्व के समस्त धर्मों का आदर्श है। अंग्रेजी में धर्म के लिये जो रिलीजन शब्द का प्रयोग हुआ है उसकी उत्पत्ति लैटिन के रैलीयेअर इनफिनीटिव से हुई है। रि का अर्थ है बैक अर्थात अतीत, पूर्व और लिगेएर का अर्थ है बांधना अर्थात जो पूर्व से बांधे। धर्म का प्रयोजन मनुष्य को उसके स्रोत से मूल से जोड़ना है। यदि धर्म मनुष्य के मन को उसके स्रोत पर ले जाकर, शरीर के क्रियाकलाप को समस्त क्रियाओं के मूल से जोड़कर उसके जीवन को उसके स्रोत से जोड़ देता है, तो धर्म का प्रयोजन पूरा हो जाता है। मन जीवन की धुरी है। यदि मन को उसके मूल पर ले जाया जा सके तो समस्त जीवन अपने मूल से जुड़ जाएगा और धर्म का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। धर्म एक मार्ग है या उसे कम से कम ऐसा मार्ग तो होना चाहिये जो मनुष्य की चेतना को भगवद्चेतना के स्तर तक उठा सके और मनुष्य के मन को दैवी चेतना या सार्वभौमिक मन में प्रतिष्ठित कर सके। धर्म का प्रयोजन वैयक्तिक जीवन को प्रकृति के नियमों के सामंजस्य में लाना है, जिससे विकास की धारा स्वाभाविक रूप से प्रवाहमान हो सके। धर्म को व्यष्टि और समष्टि के जीवन में समन्वय स्थापित करना चाहिए जिससे मानव जीवन के समस्त गुणों का संवर्धन हो सके। धर्म उस परम सत्ता के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे दर्शन शास्त्र प्रकाशित करता है। दर्शनशास्त्र विवेचनात्मक होता है, जबकि धर्म में भगवद् संसिद्धि के प्रत्यक्ष मार्ग का क्रियागत रूप मिलता है। किसी धर्म के कर्मकांड उसके शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं और भावातीत सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

धर्मकर्म

आज का इतिहास

1714 - टाइपराइटर इंग्लैंड के हेनरी मिल द्वारा बनाया गया।
1761 - पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया।
1782 - पहला अमेरिकी वाणिज्यिक बैंक (बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका) खुला।
1785 - फ्रेंचमैन जीन-पियरे ब्लांचर्ड और अमेरिकन जॉन जेफ्रीस एक गुब्बारे में हवा से अंग्रेजी चैनल को पार करने वाले पहले बने।
1789 - अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मतदान किया।
1789 - संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति चुनाव, 1788-89 और हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव के चुनाव आयोजित किए गए।
1793 - स्वीडन में ईबेल दंगा शुरू हुए।
1797 - पहले आधिकारिक इतालवी तिरंगे को सिसाडेन गणराज्य की सरकार ने अपनाया था।
1890 - विलियम बी. परविस को फाउंटेन पेन का आविष्कार का पेटेंट मिला।
1927 - पहली ट्रांस-एटलांटिक व्यावसायिक टेलीफोन सेवा न्यूयॉर्क से लंदन के बीच शुरू हुई।
1937 - नीदरलैंड की राजकुमारी जुलियाना ने हेग में लिपपे बायस्टरफर्ड के प्रिंस बर्नहार्ड से शादी की।
1940 - शीतकालीन युद्ध-फिनिश 9 वें डिवीजन ने रोका और दर-सुओमुस्सालमी सड़क पर भारी सोवियत सेनाओं को नष्ट कर दिया।
1943 - वाई-फाई के जनक मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन हुआ।
1948 - एयर नेशनल गार्ड के पायलट थॉमस मेंटल ने केंटकी के फोर्ट नॉक्स के पास यूएफओ का पीछा करते हुए अपनी पी -51 मस्टैंग को बुरी तरह कुचल दिया।
1950 - डेवनपोर्ट के आयोवा शहर के मर्सी अस्पताल में आग लगने से 41 मरीजों की मौत हुई।

आत्महत्या की बढ़ती घटना में तनाव मुख्य कारण व शांति से इसका निदान

-संजय गोस्वामी-

आज आत्महत्या की घटना मीडिया में लागातार देखने को मिल रही है जो अधिकतर तनाव के कारण हो रहा है हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली शहर के रहने वाले एक स्कूली छात्र ने दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या कर ली. छात्र ने सुसाइड से पहले एक नोट में लिखा था कि वह शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दि उधर हरियाणा के सिरसा में जेल वार्डन ने की आत्महत्या. डीएसपी समेत दो अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप. जेल वार्डन सुसाइड लेटर में डीएसपी के नाम सामने आए।

एक चौंकाने वाली घटना में दिल्ली के कालकाजी में एक 52 साल की महिला और उसके दो बेटों ने आत्महत्या कर ली। तनाव, टेंशन, एंक्जाइटी, स्टैªस जैसे शब्द आज की भागदौड़ की जिंदगी में प्रायः सुनने को मिल जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी 'टेंशन' का प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति भी। यह तनाव अथवा टेंशन ऐसी क्या चीज है जिसने प्रायः मनुष्य को अपने जाल में जकड़ लिया है। यह तनाव मन से संबंधित एक स्थिति है जो लगातार बनी रहने पर प्राणघातक हो सकती है। प्राचीन काल में यह तनाव किसी-किसी व्यक्ति में देखने को मिलता था लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यह अपवादस्वरूप ही किसी में न हो। जिस व्यक्ति में आज तनाव नहीं है, वह व्यक्ति आज समाज के समक्ष आश्चर्य का विषय बन जाता है। अभी कुछ समय पूर्व'हिंदुस्तान' में प्रकाशित एक सर्वे में बताया गया था कि मानसिक रोगियों की संख्या में लगातर वृद्धि हो रही है। 'तनाव जैसे रोग आधुनिक वैज्ञानिक युग की देन है।' ऐसा कहना अतिशयोक्तिपूण न होगा।

जहां वैज्ञानिक युग के नए-नए आविष्कार व्यक्ति में तनाव-वृद्धि में सहायक हो रहे हैं, वहीं उसकी नकारात्मक सोच, अनियंत्रित जीवन-शैली भीतनाव-वृद्धि कर रही है। प्रश्न किया जा सकता है कि नकारात्मक सोच और अनियंत्रित एवं अनियमित जीवन-शैली तो तनाव में वृद्धि करती है किंतु वैज्ञानिक आविष्कार कैसे? आप ही बताइये कि विज्ञान के नित नए आविष्कार जैसे फ्रिज, टेलीफोन, कारटेलीविजन, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर, एक से एक फीचर वाले मोबाइल, और भी न जाने क्या-क्या, इन सभी चीजों ने व्यक्ति को सुविधाभोगी बना दिया है। आज के समय में हर व्यक्ति इनको पाना चहता है लेकिन इन्हें पाने के लिए चाहिए पैसा। यदि उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास ये सब चीजें नहीं होंगी। और यदि वह यह सब पाना चाहता है तो उसे इकट्ठा करना होगा पैसा, पैसे को एकत्रित करने के लिए उसे मारामारी करनी पड़ती है। अगर इस सब बात का एक वाक्य में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए की जाने वाली भागमभाग तनाव वृद्धि का एक बड़ा कारण बन रही है। इसप्रकार लगातार भागदौड़ करने का परिणाम होता है कि वह ढंग से सो नहीं पाता और जब वह सो पाता है, तो सवेरे समय पर उठ नहीं पाता। जब उसकी आंख खुलती है और वह घड़ी देखता है तो वह समय आफिस पहुंचने का है। अब उसका तनाव बढ़ने लगता है, समय पर आफिस पहुचने के लिए वह काम को जल्दी-जल्दी करने लगता है जिससे कई काम हो जाते हैं और कई आवश्यक और महत्वपूर्ण काम करने भूल जाता है। उन कामों की याद उसे ऑफिस पहुंचने पर आती है लेकिन अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ तनाव के। जब ऐसी स्थिति लगातार बनी रहती है, तो अब यह मन से उतरकर शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव डालने लगती है। उसका प्रभाव शरीर पर कुछ यों दिखने लगता है-व्यक्ति को भूख नहीं लगती, उसे नींद नहीं आती, मांसपेशियों में जकड़न बनी रहती है, हृदय की धड़कन बढ़ी रहती है, सीने में जब-तब दर्द हो जाता है, बार-बार पेशाब जाने की इच्छा होती रहती है, खाने-पीने और सोने की आदतों में अजीबोगरीब परिवर्तन आने लगता है, रक्तचाप कम या अधिक होने लगता है, कब्ज की शिकायत हो जाती है, कभी-कभी अस्थमा का आक्रमण हो जाता है, चिडचिड़ापन और क्रोध बढ़ जाता है, सिरदर्द रहने लगता है, कभी-कभी बेहोशी भी आ जाती है। व्यक्ति अगर विद्यार्थी है तो उसका मन पढ़ने से हटने लगता है, वह नर्वस रहने लगता है, एकाग्रता घट जाती है, गैस भी बनने लगती है, काम करने का मन नहीं करता, अकेले रहने का जी चाहने लगता है अथवा वक्त बाहर ही गुजारने का मन करने लगता है।

कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि मन से संबंध रखने वाला तनाव शरीर को विभिन्न रोगों से ग्रस्त कर देता है। इस बात को भलीभांति अपने मन में बिठा लें। इस बात पर बार-बार चिंतन आपको तनावरहित अवश्य कर देगा। लेकिन हां, अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से करें। कभी-कभी पहले प्राप्त असफलता व्यक्ति को निराश करती है, उसमें तनाव की वृद्धि करती है। ऐसे समय में क्या करें? क्या पहले की असफलता को याद करके तनाव में रहें? नहीं आपको ऐसा नहीं करना। ऐसे में आपको तिनका लेकर बार-बार चढ़ने वाली चींटी की कहानी को याद रखना चाहिए। कहानी है-एक बार एक चींटी एक तिनका लेकर दीवार पर चढ़ती है। वह अभी थोड़ी ही दूर चढ़ी थी कि वह नीचे आकर गिर जाती है। वह फिर दोबारा चढती है और इस बार वह पहले से अधिक ऊपर चढ जाती है लेकिन इस बार भी वह फिर नीचे गिर जाती है। ऐसा ही तीसरी, चैथी, पांचवीं, छठी.....बार और न जाने कितनी बार होता है। पर चींटी को भी जिद है कि उसे वह तिनका लेकर ऊपर चढ़ना ही है। एक समय आता है कि चींटी तिनका लेकर चढ़ने में सफल हो जाती है। बार-बार सोचें कि जब चींटी अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकती है तो आप क्यों नहीं। तो साथियों, असफल होने पर हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं, असफल होने के कारणों पर गंभीरता से चिंतन कर उन्हें दूर करें। फिर दोगुने उत्साह से काम का शुभारंभ करें। एकाग्रचित्त होकर काम करने से काम शीघ्र संपन्न होता है, इस बात का सदा ध्यान रखें। तनाव को अपने जीवन से दूर किया जा सकता .बिल्कुल सकारात्मक है।

सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन में यह बातबैठानी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः व्यक्ति का पहला कर्तव्य है कि वह अपना शरीर स्वस्थ रखे। शरीर स्वस्थ रहता है संतुलित भोजन से। इसलिए संतुलित आहार के प्रति व्यक्ति को अपनी रुचि बढानी चाहिए। प्रातः की शुरुआत ही संतुलित और शक्तिवर्धक नाश्ते के साथ होनी चाहिए। यह आहार मन की एकाग्रता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। डिब्बाबंद आहार शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं क्योंकि इनमें वसा, नमक, कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है। अतः इस आहार के स्थान पर फल, दलिया, कार्नफ्लैक्स, साबुदाना जैसे पदार्थों का प्रयोग बढायें। ये आहार आपके पेट को ठीक रखते हैं। गहरी एवं सुखद नींद तनाव को दूर करती है। बिना किसी कारण यदि नींद आने में बाधा आती है ता डॉक्टर को दिखायें। शारीरिक व्यायाम, योग एवं ध्यान का अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व ए-152, सैक्टर 63, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से प्रकाशित।
संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई.- UPHIN/2023/84499
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। e-mail: Jbttimes2021@gmail. Com

एआई सेक्टर में जॉब ग्रोथ रेट 33 फीसदी, इसके पांचों लेयर में आ रहा बड़ा निवेशः वैष्णव

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के सभी पांच एआई लेयर्स में बड़े निवेश आ रहे हैं। इस वर्ष ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में आयोजित होगा, जो पहले ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में हो चुका है। मोदी सरकार ने भारत को दुनिया भर में एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब बनाया है।

वैष्णव ने मंगलवार को जयपुर में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल समिट की तैयारियों के तहत जी20 की तर्ज पर देश के सभी राज्यों में रीजनल एआई समिट आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय और ओडिशा में ऐसे समिट सफलतापूर्वक हुए और आज राजस्थान में यह रीजनल समिट संपन्न हो रहा है। इस दौरान राजस्थान की एआई पॉलिसी का शुभारंभ किया गया साथ ही युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और छोटे उद्यमियों को एआई स्किल्स प्रदान करना है ताकि वे अपनी जिंदगी में, खासकर लघु उद्योगों में, एआई का उपयोग कर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और लाभ उठा सकें। इसी क्रम में 10 लाख युवाओं और छोटे उद्यमियों को एआई स्किल्स देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अगले एक साल में हासिल कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तकनीक को सभी तक पहुंचाने के संकल्प के तहत एआई मिशन में 38 हजार एआई जीपीयू यानी एआई कंप्यूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इससे देश में बहुत कम कीमत पर सभी को एआई सुविधाएं मिल रही हैं। भारत में एआई क्षेत्र में लगभग 70 बिलियन डॉलर का निवेश हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा निवेश है। इस मिशन में कई नए प्रयोग, नए एप्लिकेशन और नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं।

वैष्णव ने एआई के आर्किटेक्चर की पांच लेयर्स का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे ऊपर एप्लिकेशन लेयर है। इस लेयर के लिए देश की सभी आईटी कंपनियों को जोड़कर एआई के उपयोग और एप्लिकेशंस विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा और इसमें काफी सफलता मिली है। एआई क्षेत्र में नौकरियों की ग्रोथ रेट 33 प्रतिशत है। दूसरी लेयर मॉडल्स की है।

इस लेयर में दुनिया भर के 10 लाख से ज्यादा ओपन सोर्स मॉडल्स का उपयोग कर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर काम हो रहा है। तीसरी लेयर सेमीकंडक्टर चिप्स की है, जिसमें तेज प्रगति हो रही है। चौथी लेयर डेटा सेंटरों की है, जहां 70 बिलियन डॉलर का निवेश आ रहा है। आने वाला युग एआई का है और इसमें एनर्जी की बड़ी भूमिका होगी, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए शांति बिल से परमाणु ऊर्जा को खोलकर इसे एआई का बड़ा स्रोत बनाया जा रहा है। इन सभी पांच लेयर्स में बड़े निवेश के साथ भारत एआई के क्षेत्र में मजबूत स्थिति बना रहा है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट 19 एवं 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है।

इसका मुख्य केंद्र प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। समिट की गतिविधियां पूरे दिल्ली में फैली होंगी, जिसमें द्विपक्षीय बैठकें हैदराबाद हाउस और सुषमा स्वराज भवन में, अन्य आयोजन विज्ञान भवन, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और प्रमुख पांच सितारा होटलों में होंगे। सार्वजनिक गतिविधियां और प्रदर्शनियां कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क तथा दिल्ली हाट में आयोजित की जाएंगी। विदेशी मेहमान राजघाट, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का दौरा भी करेंगे। यह समिट भारत की एआई नेतृत्व क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा।

जेएनयू में भड़काऊ नारेबाजी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : विहिप

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई भड़काऊ नारेबाजी को लेकर चिंता जताई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि यह सोच कहां से आती है? इसका संरक्षक कौन है और इसका मास्टरमाइंड कौन है? इन नारों और इसके पीछे की विचारधारा की जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जेएनयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा के मंदिरों में इस तरह की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां अस्वीकार्य हैं और समाज को इससे सबक लेना चाहिए। बंसल ने कहा कि न्यायपालिका पहले ही शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के बारे में कड़ी टिप्पणियां कर चुकी है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने पूरे देश को जिहाद की आग में धकेलने की कोशिश की थी। ये लोग पिछले पांच सालों से जेल में हैं, इसलिए इससे दूसरों को सबक लेना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि जेएनयू के सुरक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस को विश्वविद्यालय परिसर में कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में शिकायत दी है। घटना सोमवार रात की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ईटानगर में अवैध धार्मिक ढांचे हटाए जाएंगे, आईएलपी प्रणाली को सख्त किया जाएगा : खांडू

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को राज्य की राजधानी में सभी अवैध धार्मिक ढांचों की पहचान करने और उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री का यह बयान युवा संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की पृष्ठभूमि में सामने आया है, जिनका आरोप है कि अवैध प्रवासी ईटानगर राजधानी क्षेत्र (आईसीआर) में अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। खांडू ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने उपायुक्तों को राज्य की राजधानी में सभी अनधिकृत धार्मिक ढांचों की पहचान करने और उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन (बीईएफआर), 1873 के तहत 'इनर लाइन परमिट' (आईएलपी) प्रणाली द्वारा संरक्षित किया गया है, जो स्वदेशी समुदायों, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए गैर-निवासियों के प्रवेश को नियंत्रित करती है। खांडू ने कहा कि राज्य सरकार अवैध प्रवासन पर अधिक प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए जल्द ही एक नयी डिजिटल आईएलपी प्रणाली शुरू करेगी। युवा संगठनों ने अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ दिसंबर में 12 घंटे का बंद आयोजित किया था। उनकी मांगों में नाहरलागुन में अवैध रूप से निर्मित 'कैपिटल जामा मस्जिद' को हटाना, अनधिकृत बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना और अवैध रूप से बसे लोगों द्वारा कथित तौर पर लगाए जा रहे साप्ताहिक बाजारों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

रिकॉर्ड तोड़ने के लिए राजनीति नहीं कीः सिद्धारमैया

मैसूरु। समाज में आज भी असमानता मौजूद है और जब तक यह समाप्त नहीं होती तथा सभी को समान न्याय नहीं मिलता, तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बात मंगलवार को मैसूरु स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरसू के शासनकाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कभी रिकॉर्ड तोड़ने के उद्देश्य से राजनीति नहीं की। यह रिकॉर्ड संयोगवश बना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें यह जानकारी तक नहीं थी कि देवराज अरसू ने कितने वर्षों तक राज्य का नेतृत्व किया था। यह सब जनता के आशीर्वाद और समर्थन से संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा करने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय में निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लंबे राजनीतिक जीवन ने उन्हें संतोष दिया है और जनता के लिए काम करना उनके लिए खुशी की बात है। उनके अनुसार राजनीति का असली अर्थ गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनके लिए काम करना है। अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था। उनकी अधिकतम इच्छा विधायक बनने की थी, लेकिन परिस्थितियों और अवसरों के चलते वे विधायक बने, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और अंततः मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने कहा कि उन्हें मिले अवसरों और जनता के विश्वास के कारण यह सब संभव हो सका।

मप्र के उज्जैन में बेकाबू जीप ट्राले से टकराई तेलंगाना-कर्नाटक के तीन युवकों की मौत

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागझिरी थाना क्षेत्र में देवास रोड पर ग्राम चंदेसरा के पास मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार जीप (टेंपो ट्रैक्स) पाइप से भरे ट्राले से टकरा गई। इस हादसे में जीप सवार तेलंगाना और कर्नाटक के तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

तेलंगाना और कर्नाटक के सभी युवक भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन के लिए उज्जैन आए थे और यहां बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद भगवान श्रीराम लला के दर्शन के लिए अयोध्या के रवाना हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नागझिरी थाना पुलिस ने बताया कि तेलंगाना के ग्राम फरीदपुर, मेहबूबनगर निवासी केबी. नरसिम्हा (20 वर्ष) अपने दोस्तों के साथ जीप (टेंपो ट्रैक्स) से महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे। जीप में कुल 13 लोग सवार थे। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे उनकी जीप जब चंदेसरा गांव के सर्विस रोड पर महादेव सर्विस एंड वाशिंग सेंटर के सामने पहुंची, तभी हाइवे पर चल रहे पाइप से भरे ट्राले के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए।

सुबह कोहरा ज्यादा था, इसी कारण गाड़ी चला रहे ड्राइवर को सड़क के किनारे खड़े पाइप से भरा ट्राला नहीं दिखा और गाड़ी की गति अत्यधिक तेज होने के कारण वह ट्राले में जा टकराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल सभी लोगों को तुरंत चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एम. नरसिम्हा (20) पुत्र बालचंद्रणा निवासी फरीदपुर तेलंगाना और जगन्नाथ (26) पुत्र बेंकेंटेस निवासी कर्नाटक डोंगरामपुर को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिवा कुमार (25) पुत्र एलप्पा निवासी फरीदपुर तेलंगाना को इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार हादसे में जीप में सवार केबी नरसिम्हा (फरीदपुर, मेहबूबनगर), रामप्पा, मलेन पुत्र नरसप्पा, अरतिद (11) पुत्र लक्ष्मण, वाहन चालक बाल मंद्रप्पा, चिन्ना कुंधाकुंटा, जिया कुमार पुत्र एलव्या और काशप्या पुत्र चित्रा रामुनु घायल हो गए। सभी को उज्जैन के चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मामूली रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। फिलहाल चार लोग अस्पताल में भर्ती है और उनका उपचार जारी है। उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पराशर ने बताया कि सभी युवक धार्मिक यात्रा पर थे। दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने ट्राला जब्त कर उसके चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बस की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत

भुवनेश्वर। ओडिशा के पुरी जिले के पिपिली इलाके में मंगलवार सुबह एक निजी बस की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतकों में से एक की पहचान शीला पटनायक के रूप में हुई है जो एक ओडिया समाचार चैनल से जुड़ी हुई थीं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा भुवनेश्वर और पुरी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 316 पर मंगलपुर के पास हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सड़क पर बिखरी रेत की वजह से महिलाओं का स्कूटर कथित तौर पर फिसल गया, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़ीं। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार निजी बस ने उन्हें कुचल दिया। अधिकारी ने बताया कि शीला पटनायक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी महिला ने मंगलपुर अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

प्रभावी और सुलभ सार्वजनिक सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा हिमाचल : सीएम सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रभावी उपयोग में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली सोसायटी (एसआईटीईजी) की आम सभा की बैठक को सोमवार शाम संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सबसे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में भी अब अधिकांश सरकारी सेवाएं "माउस के एक क्लिक" पर उपलब्ध हैं। सुक्खू ने इसे सुशासन की दिशा में मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा विकसित विभिन्न आईटी-आधारित अनुप्रयोगों और सॉफ्टवेयर की समीक्षा की और अधिकारियों को इन प्रणालियों को अधिक नागरिक-अनुकूल, सुरक्षित और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विकसित 'हिम उपस्थिति' ऐप्लिकेशन की समीक्षा करते हुए, सुक्खू ने इसकी दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का 'हिम एक्सेस पोर्टल' पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को एक महीने के भीतर अपना पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया। बयान के अनुसार, राजस्व सेवाओं तक अधिक सुगम पहुंच के लिए हिम सेवा पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित दस्तावेज सत्यापन प्रणाली को एकीकृत किया जा रहा है।

सरकार ने शहरों में 96.53 लाख लोगों को दिए मकान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 96.53 लाख आवास बेघरों को घर दिए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दी। उन्होंने कहा कि 122.20 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है और 96.53 लाख आवास बन कर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

मनोहर लाल ने एक्स पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ने भारत के लाखों परिवारों को उनके सपनों का घर प्रदान कर उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। वर्ष 2025 में इस योजना ने आवासों की स्वीकृति और निर्माण की गति को तेज करते हुए बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि घरों के निर्माण से न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है बल्कि उन्हें सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिला है। योजना ने शहरी आवासीय परिदृश्य को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और बीते एक दशक में इसने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे शहरी गरीबों को पक्का घर देना हो, प्रवासियों को किफायती किराये का आवास उपलब्ध कराना हो या मध्यम आय वर्ग के परिवारों को उनका पहला घर दिलाने में आर्थिक सहायता प्रदान करना हो, योजना ने हर स्तर पर सकारात्मक असर डाला है।

धर्मेंद्र प्रधान ने शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में 55 साहित्यिक कृतियों का किया लोकार्पण

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राजधानी में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 55 साहित्यिक कृतियों का लोकार्पण किया। इनमें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित 41 पुस्तकें तथा केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) द्वारा प्रकाशित 13 पुस्तकें और एक तिरुक्कुरल की भारतीय सांकेतिक भाषा (इंडियन साइन लैंग्वेज) श्रृंखला शामिल हैं। इन प्रकाशनों में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया और तमिल भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण शैक्षणिक और शोधपरक कृतियां सम्मिलित हैं।

इसके साथ ही तिरुक्कुरल का भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रस्तुतीकरण समावेशी भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रयास देश की भाषायी विरासत को शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र में लाने तथा सांस्कृतिक गौरव को सुदृढ़ करने की व्यापक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारतीय भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित सूची में भाषाओं को शामिल करने से लेकर शास्त्रीय ग्रंथों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद और मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन देने तक निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनेक प्रयासों के बावजूद भारतीय भाषाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं।

प्रधान ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भाषायी विविधता इसकी शक्ति है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को संरक्षित किया जाए तथा भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने दोहराया कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और ये समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि तिरुक्कुरल का भारतीय सांकेतिक भाषा में समावेशन समावेशी भारत की परिकल्पना को सशक्त करता है, जहां ज्ञान तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित हो। उन्होंने इसे भारत के बौद्धिक साहित्य में एक मूल्यवान योगदान बताया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं में शिक्षा की दिशा को आगे बढ़ाती है और भारत 'एकता में विविधता' का सजीव उदाहरण है। उन्होंने औपनिवेशिक काल की मैकाले मानसिकता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता ने सदैव भाषाओं को संवाद और सांस्कृतिक सौहार्द के सेतु के रूप में देखा है।

प्रधान ने भारतीय भाषा समिति, उत्कृष्टता केंद्रों, सीआईआईएल और सीआईसीटी को भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए उनके प्रयासों पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चामू कृष्ण शास्त्री, सीआईआईएल के निदेशक प्रो. शैलेन्द्र मोहन, सीआईसीटी के निदेशक प्रो. आर. चंद्रशेखरन, सलाहकार (लागत) मनमोहन कौर सहित शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस को राम नाम से ही आपत्ति : मदन राठौड़

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 'विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन' (वीबी – जी राम जी) के नाम पर विरोध जताने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि कांग्रेस को राम नाम पर ही आपत्ति है। राठौड़ ने यहां पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि 'कांग्रेस को राम नाम से ही आपत्ति है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने रोजगार और आजीविका मिशन में विकसित भारत जोड़ते हुए नया कानून बनाया, तो इसमें विपक्ष को ऐतराज नहीं होना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि योजनाओं के नाम तो कांग्रेसियों ने स्वयं ने बदले और अपने एक ही परिवार के लोगों को खुश करने के लिए उनके नाम से योजनाएं शुरू कर दीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना का नाम राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना किया, फिर मनमोहन सरकार ने नरेगा और मनरेगा किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आवास योजना का नाम ग्रामीण आवास योजना से बदल कर इंदिरा आवास योजना कर दिया।

राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने हर योजना में गांधी-नेहरू परिवार का नाम जोड़ने का काम किया, करीब 600 योजनाओं के नाम इन कांग्रेसियों ने बदले जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसी भी योजना का नाम अपने या किसी के नाम पर जोड़ने की बजाए सेवा, सनातन से जोड़ने का काम किया है। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार राठौड़ ने कहा कि रोजगार योजना के इस नए कानून से न केवल जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि विकसित भारत के लिए विकसित ग्राम पंचायत बनाने के अभियान को गति भी मिलेगी। राठौड़ ने कहा कि भाजपा गांव और गरीब के कल्याण को प्राथमिकता देती है। इस कानून के माध्यम से गांव के जरूरतमंद गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। इससे गांव विकसित होंगे और विकसित भारत के साथ कदमताल कर सकेंगे। राठौड़ ने आरोप लगाया कि राज्य से कांग्रेस के सांसदों ने अपने 'राजनीतिक आकाओं' को खुश करने के लिए सांसद निधि का बिना वजह इस्तेमाल किया जो उनकी क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी है।

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य में पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण होगा आसान

परिवार के बीच दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में राहत अब व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियां भी शामिल

- पारिवारिक सदस्यों को दान दी गई संपत्ति पर देय होगा अधिकतम 5,000 स्टाम्प शुल्क
- व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर मिली राहत, शहरी और गांव सभी जगह होगा लागू

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल संपति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में दी जा रही छूट के दायरे को और व्यापक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से अब पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी।

अभी तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दान विलेखों पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार हस्तांतरण पत्र (कन्वेयंस डीड) की भांति स्टाम्प शुल्क देय होता है, जबकि रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार अचल संपत्ति के दान विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की 3 अगस्त 2023 की अधिसूचना के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी कि यदि अचल संपत्ति का दान परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क में छूट देते हुए अधिकतम 5,000 ही लिया जाएगा। यह छूट अब तक केवल कृष्य एवं आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी। योगी कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इस छूट को पारिवारिक सदस्यों के मध्य व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे परिवारों के बीच संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम खर्चीली हो जाएगी। प्रदेश के स्टांप तथा पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि 2022 से पहले तक परिवार के रिश्ते में यदि कोई प्रॉपर्टी देता था तो पूरे सर्किल रेट के बराबर स्टाम्प शुक्ल देना पड़ता था। 2022 में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय हुआ कि पारिवारिक रिश्तों में यदि कोई प्रॉपर्टी दान की जाती है तो उस पर फिक्स्ड 5 हजार रुपए स्टांप लगेगा। लेकिन यह दान केवल आवासीय और कृषि पर लागू था, लेकिन अब यह नियम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी लागू कर दिया गया है।

शहर के अंदर अब तक यह 7 प्रतिशत और गांवों में 5 प्रतिशत था, लेकिन अब गांव या शहर कहीं भी आपको केवल 5 हजार रुपए ही भुगतान करना है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, पूर्व में जारी अधिसूचना में उल्लिखित संबंधियों की परिभाषा एवं अन्य प्रावधानों को भी और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिससे नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। यह छूट संबंधित अधिसूचना के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले को आम जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पारिवारिक संपत्ति के वैधानिक हस्तांतरण को प्रोत्साहन मिलेगा और विवादों में भी कमी आएगी।

जीसीसी नीति-2024 की एसओपी-2025 को योगी कैबिनेट की हरी झंडी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमावली-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश को वैश्विक निवेश, उच्च स्तरीय सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में नई गति मिलेगी। कैबिनेट से अनुमोदित नियमावली के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह नियमावली जीसीसी नीति-2024 के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट के निर्णय के विषय में बताया कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिसके चलते निवेश करने के लिए उद्योग घराने और मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे संपर्क में हैं। जीसीसी नीति हमारे लिए बहुत लाभप्रद है और आज हम इसकी एसओपी लेकर आए हैं। यूपी में जीसीसी के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 21 कंपनियों ने इसमें निवेश प्रारंभ कर दिया है। इसके माध्यम से प्रदेश में व्यापक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नियमावली के अनुसार, जीसीसी किसी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित एक कैप्टिव इकाई होगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास , वित्त, मानव संसाधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और नॉलेज सर्विसेज जैसे रणनीतिक कार्यों का निष्पादन करेगी। इस नियमावली में जीसीसी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इनमें फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट अथवा प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी, पेरोल और भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं नवाचार प्रोत्साहन के साथ-साथ केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं। वित्तीय लाभ के अतिरिक्त, जीसीसी इकाइयों को तकनीकी सहायता समूह, इंडस्ट्री लिंकेज सपोर्ट, विनियामक सहायता, आवेदन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, अनुमोदन एवं प्रोत्साहन वितरण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कुशीनगर और झांसी में नए उप निबंधक कार्यालय भवनों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत कैबिनेट ने जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में उप निबंधक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम बसहिया उर्फ कप्तानगंज स्थित तहसील परिसर की भूमि में से 0.0920 हेक्टेयर (920 वर्गमीटर) भूमि को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में उप निबंधक कार्यालय जीर्ण-शीर्ण भवन में संचालित है, जिसे ध्वस्त कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने झांसी में उप निबंधक कार्यालय सदर एवं अभिलेखागार के निर्माण हेतु पुरानी तहसील परिसर, मौजा झांसी खास स्थित आराजी संख्या 3035 में से 0.0638 हेक्टेयर (638 वर्गमीटर) भूमि को राजस्व विभाग से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को आवंटित/हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की। दोनों ही मामलों में भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क से तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

जेएस विश्वविद्यालय का परिसमापन, आईआईएमटी विश्वविद्यालय के ग्रेटर नोएडा ऑफ-कैंपस को मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। एक तरफ, योगी कैबिनेट ने जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद (जनपद फिरोजाबाद) के परिसमापन को मंजूरी दी है तो वहीं आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ के ग्रेटर नोएडा में ऑफ-कैंपस को संचालन प्राधिकार पत्र (एलओपी) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहा बाद के परिसमापन के प्रस्ताव की मंजूरी के निर्णय की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए बीपीएड पाठ्यक्रम की फर्जी और बैक डेट में मार्कशीट व डिग्रियां जारी की गईं, जिनका उपयोग राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किया गया। इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस की जांच, कुलाधिपति एवं कुलसचिव की गिरफ्तारी तथा शासन स्तर पर गठित जांच समितियों की आख्या में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। मंत्री ने बताया कि जेएस विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसमें डिग्री प्रदान करने की शक्ति का दुरुपयोग, संगठित अपराध के रूप में फर्जी अंकतालिकाओं एवं डिग्रियों का वितरण, आवश्यक भूमि मानक का पालन न करना तथा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अनिवार्य विवरण उपलब्ध न कराना शामिल है। इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत योगी सरकार ने जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के परिसमापन का निर्णय लिया है।

परिसमापन के पश्चात विश्वविद्यालय के समस्त अभिलेख डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के संरक्षण में रखे जाएंगे तथा उन्हीं अभिलेखों के आधार पर पूर्व में निर्गत मार्कशीट एवं डिग्रियों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। साथ ही, परिसमापन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संचालन हेतु धारा 55(6) के अंतर्गत त्रि-सदस्यीय अंतरिम समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इकाइयों को मामला-दर-मामला आधार पर प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इकाइयों को 'मामला-दर-मामला' आधार पर प्रोत्साहन देने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि इस प्रोत्साहन में ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 10 साल तक की छूट, उत्तर प्रदेश के निवासी पेशेवर लोगों को अधिकतम दो हजार रुपये प्रतिमाह कर्मचारी भविष्य निधि की 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, जल शुल्क में छूट और बिजली के बिल में भी डेढ़ रुपए प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति 10 साल के लिये दिये जाने की व्यवस्था है। खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए थे उनमें से एक ई-स्टांपिंग वाला प्रस्ताव स्थगित हो गया। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ रही है और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए एसओपी को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 21 कंपनियों ने निवेश शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पंचायत चुनाव में शराब बांटने पर सामाजिक बहिष्कार का फैसला

बागपत। जनपद के ढिकौली गांव में जिला जाट सभा की पंचायत में पंचों के साथ-साथ आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों ने चुनाव के दौरान किसी भी कीमत पर शराब नहीं बांटने की शपथ ली। पंचायत में शराब बांटने वाले प्रत्याशी का सामाजिक बहिष्कार करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिला जाट सभा अध्यक्ष, अधिवक्ता सोमेन्द्र ढाका के आवास पर रविवार को नशा मुक्त समाज के संकल्प के साथ आयोजित की गई इस पंचायत में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी ढाका ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को दी। पंचायत आयोजक सोमेंद्र ढाका ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शराब मुक्त बनाने के लिए यह पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें किसान नेता अन्नू मलिक, रामछेल पंवार, विक्रम आर्य, संदीप प्रधान, विनय ढाका, जयकुमार और राजू के अलावा खाप मुखिया, प्रत्याशी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत में समाज सुधार के लिए नशे को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया गया और सभी से इस दिशा में संकल्प लेने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी शराब का वितरण कर समाज को दूषित करने का प्रयास करेगा, तो उसका मिलकर बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे लोगों ने कहा कि चुनाव में हार स्वीकार्य है, लेकिन शराब बांटकर जीत हासिल करना स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि कोई शराब के नाम पर वोट मांगने आएगा तो उसे गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

डॉ प्रवीण तोगड़िया ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की वकालत

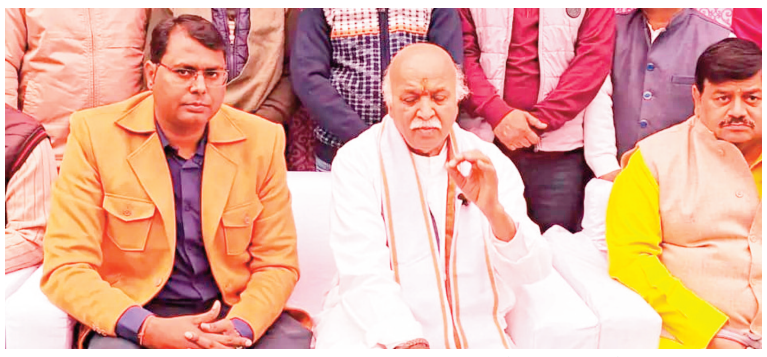

बिजनौर। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया ने बिजनौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देश में एक वर्ग की बढ़ती आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की।

तोगड़िया ने नुमाइश मैदान स्थित एक निजी आवास पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बजरंग दल, महिला परिषद और ओजस्वी जैसे चारों संगठनों ने राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदुओं के लिए व्यापक कार्य शुरू किए हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य 'हिंदू ही आगे, हिंदू सुरक्षित, हिंदू समृद्ध, सम्मानित हिंदू' है। तोगड़िया ने जोर देकर कहा कि जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है, तब तक वे सुरक्षित हैं। उन्होंने बिजनौर, सहारनपुर और रामपुर जैसे क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या में तेजी से गिरावट पर चिंता जताई। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि कानून बनने के एक वर्ष बाद किसी परिवार में तीसरा या चौथा बच्चा जन्म लेता है, तो उन्हें सरकारी राशन, स्कूल में प्रवेश, सरकारी अस्पताल में इलाज, बैंकों से ऋण और किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

साथ ही उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया जाना चाहिए। संगीत सोम को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी देने से सोम नहीं डरने वाले है हम हर कदम पर उनके साथ है | इस अवसर पर उनके साथ विनय चौधरी, अनुज शर्मा, विकास शर्मा, राहुल वर्मा आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे |

राहुल गांधी मानहानि मामले में 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

सुलतानपुर। जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले मे मंगलवार को सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने गवाह राम चंद्र दुबे से जिरह की। इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि नियत की है। वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार अब 313 के तहत कोर्ट अब राहुल गांधी को तलब करेगी। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछले पांच वर्षों से अदालती कार्यवाही चल रही है। इस मामले में राहुल गांधी के कोर्ट में पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को राहुल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उसी समय से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। अब तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई हैं, जबकि दूसरे गवाह से जिरह जारी है। अक्सर हड़ताल और गवाहों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।

मंत्रिमंडल ने वैश्विक क्षमता केंद्र नीति की नियमावली को दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति...2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नियमावली (एसओपी)...2025 को मंजूरी दे दी। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश को वैश्विक निवेश, उच्च स्तरीय सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल से अनुमोदित नियमावली के तहत 'इन्वेस्ट यूपी' को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

यह नियमावली जीसीसी नीति-2024 के लागू होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिसके चलते निवेश करने के लिए औद्योगिक घराने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां राज्य सरकार के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश में जीसीसी के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। चालू वित्त वर्ष में 21 कंपनियों ने इसमें निवेश शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से प्रदेश में व्यापक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि इस नियमावली में जीसीसी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इनमें फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टाम्प कर में छूट अथवा प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय सब्सिडी, पेरोल और भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं नवाचार प्रोत्साहन के साथ-साथ मामला-दर-मामला आधार पर विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं।

गुप्ता ने बताया कि वित्तीय लाभ के अतिरिक्त, जीसीसी इकाइयों को तकनीकी सहायता समूह, इंडस्ट्री लिंकेज सपोर्ट, विनियामक सहायता, आवेदन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, अनुमोदन एवं प्रोत्साहन वितरण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि इसके तहत मिलने वाले सभी प्रोत्साहन केंद्र सरकार की किसी भी योजना अथवा नीति के तहत उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त होंगे। स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त विभाग के नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।

ज़हरीला फल खाने से तीन बच्चों की मौत

वाराणसी। जिले के मिर्जामुराद क्षेत्र में खेलते समय कथित तौर पर जहरीला फल खाने से तीन बच्चों की मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त (गोमती जोन) आकाश पटेल ने मंगलवार को बताया कि मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के करधना इलाके में रविवार को कुछ बच्चे एक साथ खेल रहे थे। इसी दौरान उनमें से तीन बच्चों ने अनजाने में कनेर का फल खा लिया। उन्होंने बताया कि कनेर का फल जहरीला होता है और उसे खाने के तुरंत बाद तीनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई।

उनमें से दो की मौत रविवार को ही हो गई और उनके माता-पिता ने पुलिस को बिना बताये अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरे बच्चे की मौत सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। पटेल ने बताया कि इसके बाद अस्पताल ने पुलिस को सूचना भेजी, जिससे यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया। उन्होंने बताया कि स्थानीय लंका पुलिस थाने द्वारा पंचनामा प्रक्रिया के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पीड़ितों के साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने फल नहीं खाया था और वे पूरी तरह ठीक हैं। हालांकि, एहतियात के तौर पर उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। पटेल ने कहा, ''परिवारों की तरफ से किसी भी गड़बड़ी की कोई जानकारी या शिकायत नहीं है। ऐसा लगता है कि यह घटना बच्चों द्वारा खेलते समय अनजाने में जहरीला फल खाने से हुई है। इलाके में स्थिति सामान्य है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है।''

बिजली का खंभा गिरने से सात वर्षीय बच्चे की मौत

बलरामपुर। जिले के एक गांव में बिजली का खंभा सड़क से गुजर रहे सात वर्षीय बच्चे पर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तुलसीपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना सोमवार शाम गैसड़ी थाना क्षेत्र के मझोली गांव में उस समय की जब विकास साइकिल से घर लौट रहा था। उन्होंने बताया कि बबलू ओझा अपने घर के सामने बबूल के पेड़ को काट रहा था तभी उसकी एक डाल बिजली के खंभे पर गिर गई, जिससे खंभा टूटकर सड़क से गुजर रहे विकास पर गिर गया। क्षेत्राधिकारी के अनुसार, गंभीर रूप से घायल बच्चे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि बच्चे के परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती 2021 के तहत निदेशक बेसिक शिक्षा के द्वारा अपनाई जा रही नियुक्ति प्रक्रिया की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और अगली सुनवाई की तिथि 12 जनवरी नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया है। कृपा शंकर सहित 50 सफल अभ्यर्थियों ने 01 मार्च .2021 को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन, शिक्षा निदेशक बेसिक के 03नवम्बर 25 के सर्कुलर के पैराग्राफ 11 घ के परिशिष्ट 4 और काउंसलिंग के लिए जारी की गयी अनंतिम सूची को भी चुनौती दी है। आरोप है कि अनुसूचित जाति को 21 %, अनुसूचित जनजाति को 2%, ओ बी सी को 27% और 10% ई डब्ल्यू एस को वर्टिकल आरक्षण और दिव्यांगों, महिलाओं , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को होरिजेंटल आरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे वे नियुक्ति पाने से वंचित हो रहे हैं।

ग्रीन एनर्जी से संचालित होगी लखनऊ की एआई सिटी

- डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वच्छ ऊर्जा होगी अनिवार्यता
- सोलर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा मॉडल में दी जाएगी प्राथमिकता
- सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए निवेश और तकनीक दोनों पर किया जायेगा फोकस

लखनऊ। लखनऊ में प्रस्तावित एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सिटी को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी आधारित मॉडल पर विकसित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में ऊर्जा की आपूर्ति सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ स्त्रोतों से की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य एआई और डेटा आधारित तकनीकों के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण को समान रूप से प्राथमिकता देना है।प्रदेश सरकार के अनुसार एआई सिटी में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ऊर्जा जरूरतें केवल पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर नहीं होंगी। इसके लिए सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ऊर्जा लागत भी नियंत्रित रहेगी। यह मॉडल भविष्य की तकनीकी परियोजनाओं के लिए एक मानक के रूप में काम करेगा। एआई परियोजना में ग्रीन हाइड्रोजन को भी अहम स्थान दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना एआई सिटी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, औद्योगिक संचालन और स्मार्ट सुविधाओं में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की है। इससे उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल होगा जो हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ऊर्जा को व्यवहारिक स्तर पर अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाये तो उत्तर प्रदेश लीडर स्टेट के रूप में नजर आता है। एआई सिटी में डेटा सेंटर्स को वैश्विक पर्यावरण और ऊर्जा दक्षता मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी आधारित डेटा सेंटर्स से प्रदेश को वैश्विक तकनीकी कंपनियों का भरोसा मिलेगा। प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के अनुसार निवेशक अब उन स्थानों को वरीयता दे रहे हैं, जहां पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का स्पष्ट रोडमैप हो और उत्तर प्रदेश इसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एआई सिटी के विकास में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अनिवार्य किया जाएगा। भवन निर्माण में ऊर्जा कुशल सामग्री, प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम उपयोग और जल संरक्षण से संबंधित प्रणालियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि निजी वाहनों पर निर्भरता को घटाया जाए और प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।योगी सरकार का प्रयास है कि एआई सिटी परियोजना के लाभ को केवल प्रोद्योगिकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने दिया जाए।

स्वच्छ ऊर्जा आधारित विकास से स्थानीय स्तर पर बेहतर पर्यावरण, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। एआई सिटी को इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि वह तकनीक, उद्योग और समाज तीनों के लिए टिकाऊ समाधान प्रस्तुत कर सके।

सुरेश कलमाड़ी का सफर: वायु सेना के पायलट से लेकर भारत के अग्रणी खेल प्रशासक तक

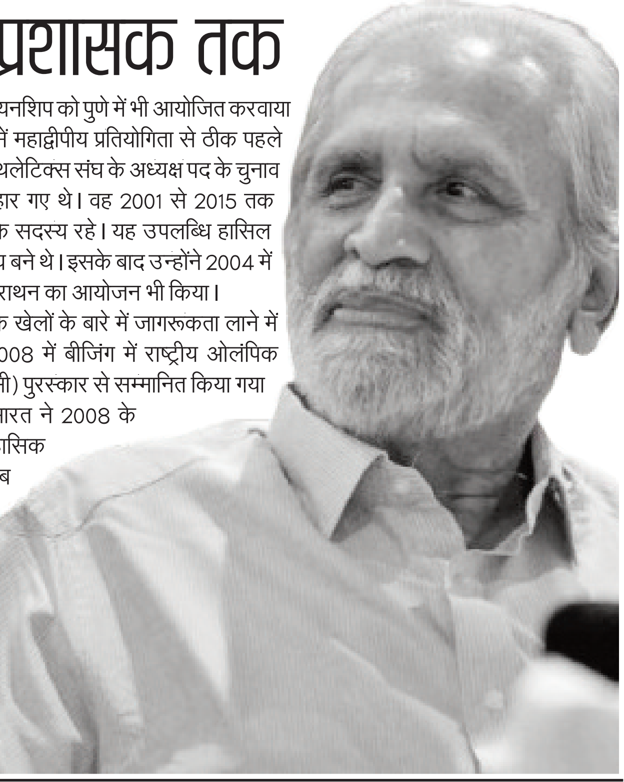

नई दिल्ली। सुरेश कलमाड़ी बेहद कुशल प्रशासक थे लेकिन इसके साथ ही उनका विवादों से भी नाता रहा और उन्हें हमेशा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वह दो दशक से अधिक समय तक विभिन्न भूमिकाओं में भारत के सबसे प्रभावशाली खेल प्रशासकों में से एक रहे। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के पूर्व अध्यक्ष कलमाड़ी का आज सुबह पुणे में निधन हो गया। वह बेहद करिश्माई व्यक्ति थे, जिनकी भारतीय खेलों पर पकड़ ने सफलता और विवाद दोनों को जन्म दिया। मद्रास (अब चेन्नई) में 1944 में जन्मे कलमाड़ी ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने बाद में इस शहर का संसद में प्रतिनिधित्व किया। लेकिन राजनीति में प्रवेश करने या खेल प्रशासन में आने से पहले कलमाड़ी ने 1964 से 1974 तक भारतीय वायु सेना में सेवा की। उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले वायुसेना में पहले एक कमीशन पायलट के रूप में और फिर एक प्रशिक्षक के रूप में काम किया।

शरद पवार की नजर उन पर पड़ी और उसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्हें पुणे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और बाद में उन्होंने संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस के विभाजन के बाद कलमाड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बने रहे तथा 1982, 1988, 1994 और 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रहे।

▶▶ सुरेश कलमाड़ी के नेतृत्व में भारत ने कई प्रमुख प्रतियोगिताओं की मेजबानी की जिनमें 2003 के एफ्रो एशियाई खेल, 2008 के राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल के अलावा 1989 और 2013 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप शामिल हैं।

कलमाड़ी 1996 में पुणे से लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन अगले आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2004 और 2009 के चुनावों में जीत हासिल करके शानदार वापसी की। लेकिन उन्हें खेल प्रशासक के रूप में अधिक प्रसिद्ध मिली और इसके कारण उन्हें बदनामी भी झेलनी पड़ी।

उनके नेतृत्व में भारत ने कई प्रमुख प्रतियोगिताओं की मेजबानी की जिनमें 2003 के एफ्रो एशियाई खेल, 2008 के राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल के अलावा 1989 और 2013 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप शामिल हैं। आईओए प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 1996 से 2011 तक चला। वर्ष 2011 में उन पर राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि पिछले साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी। आमतौर पर मृदुभाषी और कम बोलने वाले कलमाड़ी को इस घोटाले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रखा। वह अब तक के सबसे महंगे राष्ट्रमंडल खेलों में हुई हर गड़बड़ी का चेहरा बन गए। तब वह इसकी आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के गड़बड़ी करने के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया लेकिन उनके यह दावे जनता के आक्रोश और समाचार चैनलों की बहसों के शोरगुल में दब गए। इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा लेकिन कलमाड़ी को यहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता है। आईओए के प्रमुख के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक राष्ट्रीय खेलों को पुनर्जीवित करना था। उनके अध्यक्ष रहते हुए पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हैदराबाद और मणिपुर सहित विभिन्न स्थानों पर नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया।

वह भारतीय एथलेटिक्स से बेहद करीब से जुड़े रहे तथा इस बीच 1987 से 2006 तक 19 वर्षों तक भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान वह 1989 से 1998 तक दिल्ली में आयोजित आठ प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रैक और फील्ड सितारों को बुलाने में सफल रहे। उन्होंने पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो भारतीय एथलेटिक्स कैलेंडर का अहम हिस्सा बन गया। नयी दिल्ली ने उनके नेतृत्व में 1989 में देश के इतिहास में पहली बार एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भी की थी। वह 2001 में एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने 1990 में एशियाई ग्रां प्री एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत की। उन्होंने 2013 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप को पुणे में भी आयोजित करवाया था, लेकिन अपने गृहनगर में महाद्वीपीय प्रतियोगिता से ठीक पहले हुए चुनावों में वह एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में दहलान अल हमाद से हार गए थे। वह 2001 से 2015 तक विश्व एथलेटिक्स परिषद के सदस्य रहे। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय बने थे। इसके बाद उन्होंने 2004 में नयी दिल्ली में विश्व हाफ मैराथन का आयोजन भी किया।

कलमाड़ी को ओलंपिक खेलों के बारे में जागरूकता लाने में उनकी भूमिका के लिए 2008 में बीजिंग में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ (एएनओसी) पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके कार्यकाल में भारत ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने देश का पहला व्यक्तिगत ओ लं पि क स्वर्ण पदक जीता।

एशेज सीरीज: स्टीव स्मिथ के शतक से ऑस्ट्रेलिया मजबूत, तीसरे दिन स्टंप्स तक ली 134 रनों की बढ़त

सिडनी। एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्टीव स्मिथ के नाबाद शतक की बदौलत मजबूत स्थिति बना ली है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले के तीसरे दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 124 ओवर में 7 विकेट पर 518 रन बना लिए और इंग्लैंड पर 134 रन की बढ़त हासिल कर ली। स्टंप्स के समय कप्तान स्टीव स्मिथ 205 गेंदों पर 129 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल रहा।

उनके साथ ब्यू वेबस्टर 58 गेंदों पर 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत 91 ओवर में 6 विकेट पर 377 रन से की थी। उस समय स्टीव स्मिथ 115 गेंदों पर 65 रन और कैमरन ग्रीन 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने 98वें ओवर में 400 रन पूरे किए और स्मिथ-ग्रीन के बीच 50 रन की साझेदारी 101वें ओवर में पूरी हुई। हालांकि, 108वें ओवर में तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने कैमरन ग्रीन (64 गेंदों पर 37 रन, 3 चौके, 1 छक्का) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद स्मिथ ने पारी को संभालते हुए 110वें ओवर में अपना 37वां टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने यह उपलब्धि 166 गेंदों में हासिल की। इस शतक के साथ स्मिथ एशेज इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

उन्होंने इंग्लैंड के महान खिलाड़ी जैक हॉब्स (3636 रन) को पीछे छोड़ा। इस सूची में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने एशेज में 5028 रन बनाए थे। यह स्मिथ का एशेज में 13वां शतक भी रहा, जिससे उन्होंने जैक हॉब्स (12 शतक) को पीछे छोड़ दिया। इस मामले में उनसे आगे केवल डॉन ब्रैडमैन (19 शतक) हैं। स्मिथ और ब्यू वेबस्टर ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को 100 रन के पार पहुंचाया। 121वें ओवर में स्मिथ ने जोश टंग के खिलाफ दो चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया को 500 रन के पार पहुंचाया। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया 518/7 के स्कोर पर था। इससे पहले, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 97.3 ओवर में 384 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने शानदार 242 गेंदों पर 160 रन की पारी खेली, जबकि हैरी ब्रूक ने 97 गेंदों पर 84 रन बनाए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 169 रन की अहम साझेदारी हुई। इसके अलावा रूट और विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ (46 रन) के बीच 94 रन की साझेदारी भी हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी में माइकल नेसर ने 4/60 विकेट लेकर सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया। मिचेल स्टार्क को 2/93 और स्कॉट बोलैंड को 2/85 विकेट मिले।

एशेज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एशेज इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के दूसरे दिन स्मिथ एशेज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान स्मिथ ने इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जैक हॉब्स को पीछे छोड़ा। हॉब्स ने एशेज में 41 मैचों की 71 पारियों में 3636 रन बनाए थे, उनका औसत 54.26 रहा, जिसमें 13 शतक और 15 अर्धशतक शामिल थे। स्टीव स्मिथ अब एशेज में 41 मैचों की 73 पारियों में 3644 रन बना चुके हैं। उनका औसत शानदार 56.93 का है। इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं। इस सूची में स्मिथ से आगे केवल ऑस्ट्रेलियाई महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने एशेज में 37 मैचों की 63 पारियों में 5028 रन बनाए थे। ब्रैडमैन का औसत 89.78 रहा और उन्होंने 19 शतक व 12 अर्धशतक जड़े थे। इस बीच, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट भी इस सूची में आठवें स्थान पर मौजूद हैं। पहली पारी में 160 रन की शानदार पारी खेलने वाले रूट ने एशेज में अब तक 39 मैचों की 74 पारियों में 2822 रन बनाए हैं। उनका औसत 41.50 का है, जिसमें छह शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। मैच की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में अपना 37वां टेस्ट शतक भी जड़ा। यह उनका एशेज में 13वां शतक रहा, जिससे उन्होंने जैक हॉब्स (12 शतक) को पीछे छोड़ दिया। इस मामले में स्मिथ से आगे केवल डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने एशेज में 19 शतक लगाए थे।

लक्ष्य सेन मलेशिया ओपन के दूसरे दौर में, मालविका बाहर

कुआलालंपुर। भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद मंगलवार को यहां सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में पराजित करके मलेशिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाकर नए सत्र की शानदार शुरुआत की।

पिछले सत्र के आखिर में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीतने वाले 24 वर्षीय सेन ने मलेशिया ओपन में विश्व रैंकिंग में 21वें नंबर के खिलाड़ी तेह को 70 मिनट में 21-16 15-21 21-14 से हराया। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता और वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज सेन का अगला मुकाबला फ्रांस के छठी वरीयता प्राप्त क्रिस्टो पोपोव या हांगकांग के ली चेउक यिउ के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। बाएं घुटने की चोट के कारण छह महीने के अंतराल के बाद वापसी करने वाली मालविका बंसोड़ को महिला एकल में हालांकि पहले दौर में थाईलैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन रत्चनोक इंतानोन से 11-21 11-21 से हार का सामना करना पड़ा।

कड़े संघर्ष के बाद हारी वीनस विलियम्स

वेलिंगटन। वीनस विलियम्स ने 45 साल की उम्र में भी अपने जुझारूपन का शानदार नमूना पेश किया लेकिन आखिर में वह मंगलवार को यहां ऑकलैंड ओपन डब्ल्यूटीए टूर टेनिस टूर्नामेंट में पांचवीं वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेट से हार गईं। वर्ष 2026 में अपना पहला एकल मैच खेल रही वीनस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में उन्हें 52वीं रैंकिंग की खिलाड़ी लिनेट से 6-4, 4-6, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा। लिनेट उस समय केवल दो साल की थीं जब वीनस ने पेशेवर टूर पर अपना पहला एकल मैच खेला था। मंगलवार का मैच डब्ल्यूटीए टूर पर एकल वर्ग में विलियम्स का 1101वां मैच था। उन्होंने अपने से 12 साल छोटी खिलाड़ी के सामने जिस तरह की चुनौती पेश की उससे उनका होबार्ट इंटरनेशनल और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आत्मविश्वास बढ़ेगा।

रुपया 12 पैसे चढ़कर 90.18 प्रति डॉलर पर पहुंचा

मुंबई। रुपये की विनिमय दर में पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर मंगलवार को विराम लगा और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे चढ़कर 90.18 (अस्थायी) पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर सूचकांक में गिरावट के बीच रुपया मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख और अमेरिका तथा वेनेजुएला के बीच तनाव ने घरेलू मुद्रा में तेज बढ़त पर अंकुश लगाया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.22 पर खुला और 90.08 से 90.25 के दायरे में कारोबार करने के बाद 90.18 (अस्थायी) पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे अधिक है।

रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे टूटकर 90.30 पर बंद हुआ था। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक (जिंस) अनुज चौधरी ने कहा, ''अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भू-राजनीतिक तनाव से वैश्विक बाजारों में उपजे जोखिम से बचने के रुख के कारण रुपये में गिरावट जारी रहने का अनुमान है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से रुपये पर और दबाव पड़ सकता है।'' चौधरी ने कहा, ''हालांकि, कमजोर डॉलर के साथ अमेरिकी आर्थिक आंकडें नरम रहने के बीच केंद्रीय बैंक के किसी भी हस्तक्षेप से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिल सकता है।'' इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को बताने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत टूटकर 98.21 पर रहा। अमेरिकी आईएसएम विनिर्माण पीएमआई आंकड़ा उम्मीद से कम रहने से डॉलर सूचकांक में गिरावट आई।

पीयूष गोयल ने कंपनियों से सीएसआर खर्च को कुपोषण से निपटने पर लगाने का अनुरोध किया

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कॉरपोरेट जगत से अपने सीएसआर खर्च को कुपोषण से निपटने में लगाने का मंगलवार को आह्वान किया और इसे भारत के भविष्य एवं उनके अपने व्यावसायिक हितों के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। एनडीडीबी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण निवारण में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका' विषय पर राष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन में गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को कुपोषण-मुक्त बनाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, '' देश को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गर्भावस्था और शिशु के विकास के चरण में ही कुपोषण को रोका जा सकता है।'' मंत्री ने इस क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यों की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए यह बात कही। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि कुपोषण की रोकथाम पर केंद्रित सीएसआर गतिविधियों से निवेश पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, '' यह दान नहीं है, आप अपनी कंपनी के भविष्य के मुनाफे में निवेश कर रहे हैं। अगर आप अपनी गतिविधियों को कुपोषण से जोड़ते हैं तो आप अपना ही भला कर रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनियां खुद की मदद कर रही हैं, नए बाजार, नया श्रम, नए कर्मचारी एवं भविष्य के नए उपभोक्ता तैयार कर रही हैं।'' गोयल ने कंपनियों से आग्रह किया कि वे दो प्रतिशत सीएसआर खर्च के अनिवार्य नियम को बाध्यकारी दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। उन्होंने कॉरपोरेट जगत से शहरों से बाहर निकलकर दूरदराज के क्षेत्रों तक अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का भी आह्वान किया। इस कार्यक्रम में दो सीएसआर कार्यक्रम एसएआईएल-भिलाई स्टील प्लांट के 'गिफ्टमिल्क कार्यक्रम' और आईडीबीआई बैंक के 'शिशु संजीवनी कार्यक्रम' की शुरुआत की गई। 'गिफ्टमिल्क कार्यक्रम' के तहत, छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 4,000 बच्चों को विटामिन ए और डी से युक्त सुगंधित दूध मिलेगा, जिसकी आपूर्ति एनडीडीबी द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ मिल्क फेडरेशन के माध्यम से की जाएगी।

'शिशु संजीवनी कार्यक्रम' महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में करीब 3,000 बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि शिशु अवस्था एवं गर्भावस्था के दौरान संतुलित पोषण ही कुपोषण से निपटने का एकमात्र समाधान है। उन्होंने बताया कि दूध और दुग्ध उत्पाद 25-35 प्रतिशत प्रोटीन की पूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, जो बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कृष्ण पाल गुर्जर, एस. पी. सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन के अलावा सहकारिता सचिव आशीष कुमार भूटानी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

वाहनों की खुदरा बिक्री बीते वर्ष 7.7% बढ़कर 2.81 करोड़ इकाई रही: फाडा

नई दिल्ली। देश में वर्ष 2025 के दौरान वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 7.71 प्रतिशत बढ़कर 2.81 करोड़ इकाई से अधिक हो गई। वाहन डीलरों के संगठन फाडा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) ने वर्ष 2025 के बिक्री आंकड़े जारी करते हुए कहा कि साल की सुस्त शुरुआत के बावजूद जीएसटी दरों में कटौती के बाद मांग में सुधार आया और बिक्री को मजबूती मिली।

फाडा के मुताबिक, वर्ष 2025 में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 9.7 प्रतिशत बढ़कर 44.75 लाख इकाई रही, जो एक साल पहले 40.79 लाख इकाई थी। इसी तरह, पिछले साल दोपहिया वाहनों की बिक्री 7.24 प्रतिशत बढ़कर 2.02 करोड़ इकाई पर पहुंच गई। इस दौरान तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 7.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13.09 लाख इकाई रही, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 6.71 प्रतिशत बढ़कर 10.09 लाख इकाई हो गई।

फाडा के अध्यक्ष सी एस विग्नेश्वर ने इन आंकड़ों पर कहा कि 2025 का साल दो हिस्सों में बंटा रहा। बजट में प्रत्यक्ष कर राहत और आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती जैसे अनुकूल संकेत मौजूद होने के बावजूद जनवरी से अगस्त तक बाजार सुस्त बना रहा। इस दौरान ग्राहक खर्च को लेकर सतर्क रहे और वित्त मंजूरी भी कुछ क्षेत्रों में सीमित रही। हालांकि विग्नेश्वर के मुताबिक, सितंबर में जीएसटी की दरों में कटौती लागू होने के बाद वाहन बिक्री की तस्वीर बदल गई। दरों में कटौती से खासकर छोटी कारों, दोपहिया, तिपहिया और कुछ वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें कम हो गईं। इससे ग्राहकों की धारणा सुधरी और सितंबर से दिसंबर के बीच बिक्री में साफ उछाल देखने को मिला। फाडा ने बताया कि 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी भी बढ़ी, जबकि सीएनजी वाहनों की मौजूदगी यात्री एवं वाणिज्यिक खंड में मजबूत हुई, जिससे परिवहन विकल्पों में विविधता देखने को मिली।

भावी परिदृश्य को लेकर फाडा ने कहा कि अगले तीन महीनों में 74.9 प्रतिशत डीलर बिक्री बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। त्योहारों, शादी के मौसम, रबी की बेहतर फसल और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों से मांग को सहारा मिलने की संभावना है।

बीआईएस मार्क कई सेक्टर्स में भरोसे के प्रतीक के तौर पर उभरा : प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मार्क कई सेक्टरों में भरोसे का प्रतीक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि बीआईएस सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक मजबूत विरासत है, जिसने देश की

यात्रा को आकार दिया है। मंत्री जोशी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के 79वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। प्रल्हाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि क्वालिटी एक जिम्मेदारी और एक कॉम्पिटिटिव फायदा है, जिसमें स्टैंडर्ड एक्सीलेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस करने में आसानी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरभारत के लिए बेंचमार्क का काम करते हैं। जोशी ने कहा कि बीआईएस क्वालिटी, भरोसे और एक्सीलेंस की विरासत का जश्न मना रहा है। केंद्रीय मंत्री ने जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट और मेड इन इंडिया को ट्रस्टेड बाय इंडिया और ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड में बदलने के सामूहिक संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 376 अंक फिसला

मुंबई। एशियाई बाजारों के मजबूत रुख के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में भारी बिकवाली से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स में 376 अंक की गिरावट रही जबकि निफ्टी करीब 72 अंक फिसल गया। विश्लेषकों के मुताबिक, भारत पर शुल्क बढ़ाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी से निवेशक सतर्क हो गए और कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है।

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 376.28 अंक यानी 0.44 प्रतिशत टूटकर 85,063.34 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 539.52 अंक तक लुढ़ककर 84,900.10 अंक पर आ गया था। वहीं, एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 71.60 अंक यानी 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट के शेयर में 8.62 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर तिमाही में कंपनी की राजस्व वृद्धि के आंकड़े निवेशकों को उत्साहित करने में नाकाम रहे हैं। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 4.42 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और एचडीएफसी बैंक भी नुकसान में रहे।

हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 36.25 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। इसके उलट घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,764.07 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद की। बाजार पर दबाव का एक कारण अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी रहा। उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने से वह खुश नहीं हैं और अमेरिका भारत पर शुल्क को 'बहुत जल्द' बढ़ा सकता है। इस बीच, एक सर्वेक्षण ने दिसंबर में देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर धीमी पड़ने की बात कही है।

एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज का खरीद प्रबंध सूचकांक नवंबर के 59.8 से घटकर दिसंबर में 58.0 रह गया, जो 11 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इस तरह कारोबारी भरोसा करीब साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गया।

सांस लेने में हो रही तकलीफ

हिना खान

मुंबई के प्रदूषण से सेहत पर पड़ा बुरा असर

मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा अपने तेज रफ्तार जीवन और चमक-दमक के लिए जानी जाती है। हाल के वर्षों में मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है और लोगों के लिए दिन-प्रतिदिन की जिंदगी मुश्किल बनती जा रही है। प्रदूषण ने ना सिर्फ आम लोगों की सेहत पर असर डाला है, बल्कि सेलिब्रिटी भी इससे अछूते नहीं हैं। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वह बढ़ते प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। हिना खान ने कहा, "मुंबई की बिगड़ती हवा के कारण मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्रदूषण की वजह से लगातार खांसी है और यह सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से जूझने के कारण यह मेरे लिए और भी चुनौतीपूर्ण है।" हिना खान ने कहा, "प्रदूषित हवा की वजह से मेरा बाहर निकलना और शारीरिक तौर पर कोई काम करना भी सीमित हो गया है। यह मेरे दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियों पर भी असर डाल रहा है।" अपने अनुभव को और स्पष्ट करने के लिए हिना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मुंबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का स्क्रीनशॉट साझा किया। इस स्क्रीनशॉट में शहर का एक्यूआई 209 दर्ज किया गया, जो बताता है कि हवा की गुणवत्ता 'खराब' स्तर पर है। हिना ने कैप्शन में लिखा, "क्या हो रहा है? सांस नहीं ले पा रही हूं। बाहर जाना कम कर दिया है। लगातार खांसी हो रही है। सुबह से ही हालत बहुत खराब है।" इससे पहले हिना खान ने अभिनेत्री सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में अपने कैंसर से जूझने की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बारे में भी खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया कि उनका इलाज कठिन रहा और इस दौरान उन्हें अच्छे और बुरे दोनों दिन देखने को मिले। हिना ने कहा कि उन्होंने हर तीन हफ्ते में कीमोथेरेपी ली, और कीमो के पहले हफ्ते में उन्हें बहुत दर्द होता था। लेकिन बाकी के दो हफ्ते, वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती थीं और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ वक्त बिताती थीं। हिना ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, "देखने का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जैसे ही किसी गंभीर बीमारी का पता लगाते हैं, सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी। लेकिन अनुभव करने के बाद मैंने समझा कि जीवन में बुरे और दर्दनाक दिन जरूर होते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आते हैं, जब आप अपने परिवार और प्यार के बीच सामान्य जीवन जीते हैं। यह संतुलन ही जीवन की खूबसूरती है।

इमरान खान ने जताई थी हैप्पी पटेल में काम करने की इच्छा : वीर दास

मुंबई। जानेमाने अभिनेता वीर दास ने बताया है कि अभिनेता इमरान खान बिल्कुल अलग और ना सोचे हुए तरीके से फिल्म हैप्पी पटेल का हिस्सा बने। आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस से निर्देशन की शुरुआत कर रहे वीर दास ने हाल ही में फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प पर्दे के पीछे का किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि इमरान खान कैसे बिल्कुल अलग और ना सोचे हुए तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बने। इस बारे में बात करते हुए वीर दास ने बताया कि कैसे एक साधारण सा मैसेज आगे चलकर एक मज़ेदार और रचनात्मक मौके में बदल गया, जिसने फिल्म के एक अहम किरदार को जन्म दिया। वीर दास ने उस पल को याद करते हुए कहा कि एक दिन मुझे इमरान का मैसेज आया। वो वैसे भी व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं करते उन्होंने बताया। मैसेज में लिखा था कि सुना है फिल्म अच्छी बन रही है, क्या मैं इसमें कुछ मज़ेदार कर सकता हूं?' वीर दास के अनुसार यह मैसेज उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज़ था, खासकर इसलिए क्योंकि इमरान बहुत चुनिंदा प्रोजेक्ट्स करते हैं और पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट से दूर रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच समझ और भरोसे पर आधारित बातचीत शुरू हुई। वीर दास ने बताया कि जैसे ही इमरान ने दिलचस्पी दिखाई, उन्हें लगा कि फिल्म के सेट पर उनकी वापसी को खास बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है। वीर दास ने कहा कि जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने हैप्पी पटेल की स्क्रिप्ट में उनके लिए जगह बनानी शुरू की। मैंने उनसे कहा,हां, बिल्कुल, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आपके लिए ऐसा किरदार तैयार करूंगा जो मज़ेदार और थोड़ा पागलपन भरा होगा, और कुछ ऐसा होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास ने किया है। फिल्म में मोना सिंह, शारिब हाशमी और मिथिला पालकर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे, और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

'टॉक्सिक' की पहली झलक में मेलिसा के अवतार में नजर आई रुक्मिणी वसंत

पैन-इंडिया प्रोजेक्ट 'टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्म की पहली झलक यश के दमदार लुक के साथ सामने आई थी, जिसके बाद मेकर्स एक-एक कर फीमेल कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक जारी कर रहे हैं। कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया के बाद अब फिल्म से जुड़ी एक और अभिनेत्री का लुक सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। मेकर्स ने इस बार अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत को फिल्म से इंट्रोड्यूस किया है। पोस्टर में वह मेलिसा के किरदार में दिखाई दे रही हैं। उनका लुक बेहद स्टाइलिश, रहस्यमयी और कातिलाना अंदाज़ में पेश किया गया है। वेस्टर्न आउटफिट, स्लीक हेयरस्टाइल और इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ रुक्मिणी का यह अवतार साफ संकेत देता है कि फिल्म में उनका किरदार कहानी के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। 'कांताराः चैप्टर 2' से अपनी अलग पहचान बना चुकी रुक्मिणी का यह नया लुक फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है।राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। वहीं, इंडस्ट्री में यह चर्चा भी जोरों पर है कि यश के जन्मदिन 8 जनवरी के मौके पर फिल्म का टीज़र जारी किया जा सकता है। हालांकि, मेकर्स की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

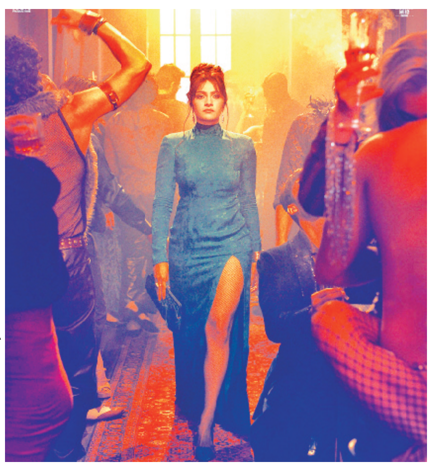

बांग्लादेश में एक और हिंदू कारोबारी की हत्या

ढाका। बांग्लादेश के नरसिंगदी शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक किराना दुकान के 40 वर्षीय हिंदू मालिक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

यह घटना सोमवार रात को हुई। इससे कुछ ही घंटों पहले बांग्लादेश के जेस्सोर जिले में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी को सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे। 'बीडीन्यूज 24' की खबर के अनुसार, पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में दुकानदार मणि चक्रवर्ती पर सोमवार रात करीब 11 बजे हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। पलाश पुलिस थाना प्रमुख (ओसी) शाहेद अल मामून ने बताया कि मणि शिबपुर उपजिला के साधरचार यूनियन निवासी मदन ठाकुर के बेटे थे। मणि चारसिंदूर बाजार में किराना दुकान के मालिक थे। हाल के सप्ताहों में मारे गए वह तीसरे हिंदू कारोबारी हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बताया कि मणि जब सोमवार रात दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार एवं स्थानीय रूप से निर्मित हथियार से वार किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मणि की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग उन्हें पलाश उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहेद ने कहा कि पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची और दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए नरसिंगदी सदर अस्पताल के शवगृह भेजा गया है। इससे पहले भी हिंदू समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। सोमवार को खुलना मंडल में जेस्सोर के केशबपुर उपजिला में अरुआ गांव निवासी 38 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी के सिर में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

यह घटना सोमवार को कपालिया बाजार में शाम करीब पौने छह बजे हुई। इसके पहले तीन जनवरी को खोकन चंद्र दास (50) पर चाकू से हमला करने के बाद उन्हें जला दिया गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह 24 दिसंबर को राजबारी कस्बे के पांगशा उपजिला में एक अन्य हिंदू व्यक्ति अमृत मंडल की जबरन वसूली के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मयमनसिंह शहर में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास (25) की ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और उनके शव को आग लगा दी। चटगांव के बाहरी इलाके रावजान क्षेत्र में 23 दिसंबर को अज्ञात लोगों ने कतर में काम करने वाले प्रवासी कामगारों सुख शिल और अनिल शिल के घर में आग लगा दी, लेकिन वे बाल-बाल बच गए।

ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर मेक्सिको ने अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका को खारिज किया

मेक्सिको सिटी। वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप के बाद मेक्सिको सरकार और विशेषज्ञों ने देश में मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों के खिलाफ एकतरफा अमेरिकी कार्रवाई की आशंका को खारिज कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको को इन गिरोहों के संबंध में चेतावनी दे चुके हैं।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम का प्रशासन अमेरिका की मांगों पर काम कर रहा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, कई लोगों का मानना है कि ट्रंप मेक्सिको को इस तरह की कई और धमकियां दे सकते हैं। इन धमकियों को मेक्सिको से और अधिक रियायतें पाने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कोई भी इस आशंका को पूरी तरह से नहीं नकार रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोई अप्रत्याशित कदम उठा सकते हैं। शीनबॉम ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंका को सोमवार को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई जोखिम है। अमेरिकी सरकार के साथ समन्वय और सहयोग कायम है। उन्होंने कहा कि मैं (आक्रमण की आशंका पर) विश्वास नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि संगठित अपराध का समाधान (विदेशी सैन्य) हस्तक्षेप से नहीं किया जा सकता। ऐसे में वेनेजुएला की तरह मेक्सिको में भी अमेरिकी कार्रवाई की आशंका को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मेक्सिको और वेनेजुएला की स्थिति एक-दूसरे से काफी अलग है। सबसे पहली बात जो मेक्सिको को वेनेजुएला से अलग करती है वह यह है कि शीनबॉम एक लोकप्रिय और वैध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं।

दूसरा पहलू यह है कि मेक्सिको अमेरिका का मुख्य व्यापारिक साझीदार है, और वहां चार करोड़ मेक्सिकन नागरिक रहते हैं। तीसरी बात, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्वीकार किया है कि मेक्सिको के साथ उच्च-स्तरीय सहयोग है। मेक्सिको के सेंटर फॉर इकनॉमिक रिसर्च एंड टीचिंग (सीआईडीई) में एक राजनीतिक विश्लेषक कार्लोस पेरेज रिकार्टके अनुसार मेक्सिको में हस्तक्षेप या सैन्य कार्रवाई से वह सहयोग बंद हो जाएगा।

ईरानः विरोध-प्रदर्शनों में अब तक '35 लोगों की मौत, 1,200 हिरासत में

तेहरान (ईरान)। ईरान में अर्थव्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति और राजनीतिक दमन को लेकर एक हफ्ते से अधिक समय से जारी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। एक मानवाधिकार एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस बीच, ईरान सरकार ने देश के पश्चिमी प्रांत ईलम में हिंसा की बात स्वीकार की है, जहां सुरक्षाबलों ने एक अस्पताल पर कथित तौर पर धावा बोला और आम नागरिकों पर गोलीबारी भी की।

अमेरिका की 'ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी' ने बताया कि ईरान के 31 प्रांतों में से 27 में 250 से अधिक स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। उसने बताया कि इन विरोध-प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 29 प्रदर्शनकारी, चार बच्चे और ईरानी सुरक्षा बल के दो सदस्य मारे गए हैं।

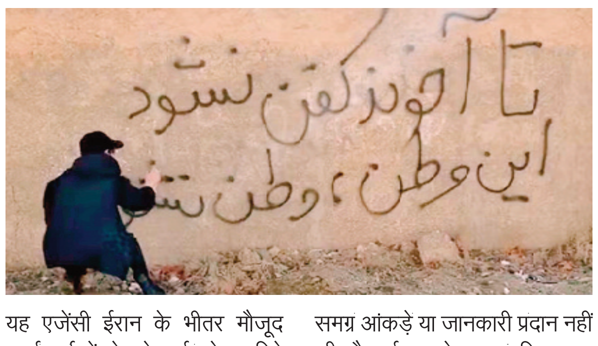

यह एजेंसी ईरान के भीतर मौजूद कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिये आंकड़े जुटाती है और अशांति के पिछले दौर के दौरान इसकी रिपोर्टिंग सही साबित हुई थी। अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'फार्स' ने सोमवार देर रात बताया कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान लगभग 250 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड बल के 45 सदस्य घायल हुए हैं।

हालांकि, ईरान सरकार ने विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में कोई समग्र आंकड़े या जानकारी प्रदान नहीं की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार रात आंतरिक मामलों के मंत्रालय को ईलम प्रांत में हो रही घटनाओं की 'गहन जांच' के लिए एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया। राजधानी तेहरान से लगभग 515 किलोमीटर दूर ईलम प्रांत के मालेकशाही काउंटी से सामने आए वीडियो में सुरक्षाबलों को आम नागरिकों पर कथित तौर पर गोलीबारी करते देखा जा सकता है।

पश्चिमी जापान में शक्तिशाली भूकंप

तोक्यो। पश्चिमी जापान में मंगलवार को शक्तिशाली भूकंप आया लेकिन इससे सुनामी आने का कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के कारण कोई बड़ा नुकसान होने या किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.2 थी और यह उत्तर-पश्चिमी जापान के शिमाने प्रांत में आया। बाद में एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। प्रांतीय राजधानी मात्सुए और तोत्तोरी प्रांत के कुछ शहर समेत आसपास के शहरों में सबसे अधिक झटके महसूस किए गए। एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर (6.2 मील) की गहराई में था। उसने साथ ही कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। हालांकि, जेएमए के अधिकारियों ने क्षेत्र के निवासियों को सचेत किया कि लगभग एक सप्ताह तक शक्तिशाली भूकंप आने का खतरा है।

वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी जोरदार धमाके, सुरक्षा बढ़ाई गई

काराकस (वेनेजुएला)। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति भवन पालासिओ डी मिराफ्लोरेस के पास गोलीबारी और विस्फोट की तेज आवाज सुनने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह घटना अमेरिकी सेना के हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के दो दिन बाद हुई है। इस बीच उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। वेनेजुएला के सुरक्षाबलों ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अमेरिका ने कहा कि इस घटना में उसका हाथ नहीं है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, सत्यापित किए गए एक वीडियो में काराकस के ऊपर एंटी-एयरक्राफ्ट फायरिंग दिखाई दे रही है। एक अन्य सत्यापित वीडियो में राजधानी में गोलीबारी की आवाज भी सुनी जा सकती है। एक नागरिक ने पुष्टि कि उसने मिराफ्लोरेस राष्ट्रपति भवन के पास उरडानेटा एवेन्यू के पास गोलीबारी की आवाज सुनी।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने गलतफहमी के कारण यह गोलीबारी की। एक सूत्र के अनुसार, राष्ट्रपति भवन के ऊपर ड्रोन दिखने पर गोली चलाई गई। उल्लेखनीय है कि एंटी-एयरक्राफ्ट फायरिंग रक्षात्मक प्रणाली है। इसका उपयोग दुश्मन के हवाई हमलों (जैसे विमान, मिसाइल या ड्रोन) को नष्ट करने के लिए किया जाता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इस घटना पर करीब से नजर रख रहा है।

इस अधिकारी ने साफ किया कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। उधर, वेनेजुएला के सूचना मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।